RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 02, अंक 08 मासिक पत्रिका
25 अगस्त 2023

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

महाविनाश से बचना है तो रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए...

आगे आये दुनिया

हमारा देश हमारा अभिमान परिवार
की ओर से स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं

हमारा देश हमारा अभिमान

अगस्त 2023

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ श्री. सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. श्री दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे • श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव,
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार • श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह • प्रदीप यादव

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	02
शुभाशीष	03
कवर स्टोरी	04-05
देश-प्रदेश	06-07
स्मरण	07
महाराष्ट्र	08
विदेश	10
राजस्थान	11
प्रदेश	12
रिकॉर्ड	13
देश	14
प्रदेश	15
इन्दौर	18
विज्ञान	19
राजस्थान	20-21
राजस्थान	22-23
इन्दौर	24
भोपाल	25
प्रदेश	32-33
देश	38-39
धर्म	40
त्यौहार	41
स्वास्थ्य	42-43
मौसम	44
जीवनशैली	45
ग्लैमर	46-47

48

दिल का दौरा पड़ने के बाद सुष्मिता ने पहली बार खुलकर की अपनी सेहत पर बात... कहा- भगवान की कृपा

संपादकीय

सरकार के प्रयासों से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार

एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जीवन रेखा बढ़ी है तो तस्वीर का धुंधला पहलू यह भी सामने आना लगा है कि जो चीजें हमें प्रकृति से आसानी से मिल जाती हैं, जिन तक सहज पहुंच है उन्हीं की डेफिसिएंसी ज्यादा होने लगी है। यदि कोरोना प्रकोप छोड़ दिया जाए तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के देशों में जीवन रेखा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के समग्र प्रयासों का परिणाम है कि अपने समय की जानलेवा बीमारियां टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, पीलिया, डायरिया आदि पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। दुनिया के देशों में बाल मृत्यु दर लगभग आधी रह गई है तो प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर भी करीब एक तिहाई रह गई है। संस्थागत प्रसव ने हालातों में तेजी से सुधार किया है। दुनिया के अधिकांश देशों में संक्रामक रोगों का असर भी कम हुआ है तो डेंगू, स्वाईन फ्लू व इसी तरह की कुछ जानलेवा बीमारियां सामने आने लगी हैं। पिछले कुछ दशकों से हमारे देश ही नहीं दुनिया के लगभग अधिकांश देशों में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके लिए वैक्सिनेशन अभियान और सरकारों द्वारा अनवरत रुप से चलाए जाने वाले अवेयरनेस और नियंत्रण अभियानों से हालातों में तेजी से सुधार हुआ है। लोगों की जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के अपवाद को अलग कर दिया जाए तो जहां 2000 में औसत आयु 67 साल होती थी वह 2019 तक बढ़कर 73 साल हो गई है। यानी की 19 सालों में छह साल अधिक जीने लगे हैं आम नागरिक। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं की। टीकाकरण और समय समय पर एनिमिया, दस्त निरोधक, कृमि नाशक दवाएं अभियान चलाकर उपलब्ध कराने से सेहत के क्षेत्र में लगातार सुधार आया है। यह वास्तव में चिकित्सा जगत की बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए और इसके लिए सरकारों व स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो पाया है।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

देश के बारे में झूठा विमर्श गढ़ने के प्रयास, सतर्क रहने की जरूरत

जुलाई 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 11 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित करते हुए 1.65 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जो जुलाई 2022 माह में 1.49 लाख करोड़ रुपए का एवं जून 2023 माह में 1.61 लाख करोड़ रुपए का रहा था। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास से संबंधित हाल ही में जारी किये गए आंकड़ों को देखने के पश्चात ध्यान में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी है। परंतु, देश के मीडिया में भारत के आर्थिक क्षेत्र में लगातार बन रहे नित नए रिकार्ड का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसके ठीक विपरीत देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, गरीब अति गरीब की श्रेणी में जा रहा है, मुद्रा स्फीति की दर अधिक हो रही है, भुखमरी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदि विषयों पर विमर्श गढ़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। भारत में झूठे विमर्श गढ़ने का इतिहास रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में भी कई प्रकार के झूठे विमर्श गढ़ने के भरपूर प्रयास हुए थे जैसे पश्चिम से आया कोई भी विचार वैज्ञानिक एवं आधुनिक है, भारत सपेरों का देश है एवं इसमें अपढ़ गरीब वर्ग ही निवास करता है, सनातन भारतीय संस्कृति रुढ़िवादी एवं अवैज्ञानिक है, शहरीकरण विकास का बड़ा माध्यम है अतः ग्रामीण विकास को दरकिनार करते हुए केवल शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, शहरी, ग्रामीण एवं जनजातीय के बीच में आर्थिक विकास की दृष्टि से शहरी अधिक महत्व के क्षेत्र हैं, विदेशी भाषा को जानने के चलते नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है, संस्कृति से अधिक तर्क को महत्व दिया जाना चाहिए, व्यक्ति एवं समष्टि में व्यक्ति को अधिक महत्व देना अर्थात व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना चाहिए (पूंजीवाद की अवधारणा), कम श्रम करने वाला व्यक्ति अधिक होशियार माना गया, सनातन हिन्दू संस्कृति पर आधारित प्रत्येक चीज को हेय दृष्टि से देखना, जैसे दिवाली के पटाखे पर्यावरण का नुक्सान करते हैं, होली पर्व पर पानी की बर्बादी होती है।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

महाविनाश से बचना है तो रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए...

आगे आये दुनिया

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन जंग के शुरू होने पर लगा था कि लड़ाई एकतरफा है। रूस के सामने यूक्रेन नहीं टिक पाएगा, किंतु हुआ सोच के विपरीत। डेढ़ साल बाद भी यूक्रेन मजबूती के साथ रूस के सामने खड़ा है। सूचनाएं आ रही हैं कि यूक्रेन अब बढ़त ही ओर है।

रूस-यूक्रेन युद्ध से हो रहे और होने वाले मानव जाति को महाविनाश से बचाने के लिए अभी रूस-अफ्रीका फ़ोरम प्रयास कर रहा है, आज जबकि इस युद्ध को रुकवाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का कोई महत्व नहीं, ऐसे में इस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। सबको अपने प्रयास करने चाहिए। डेढ़ साल से चल रहा ये युद्ध किसी भी समय परमाणु हमले की जद में आ सकता है। इस युद्ध में हिरोशिमा-नागासाकी के बाद फिर से मानव जाति के महाविनाश की कहानी लिखी जा सकती है। इसकी खास बात ये होगी कि इस बार महाविनाश हिरोशिमा नागासाकी से कई गुना भारी होगा, क्योंकि अब परमाणु बमों की क्षमता पहले से बहुत अधिक है।

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन जंग के शुरू होने पर लगा था कि लड़ाई एकतरफा है। रूस के सामने यूक्रेन नहीं टिक पाएगा, किंतु हुआ सोच के विपरीत। डेढ़ साल बाद भी यूक्रेन मजबूती के साथ रूस के सामने खड़ा है। सूचनाएं आ रही हैं कि यूक्रेन अब बढ़त ही ओर है। यूक्रेन का रूस पर बढ़त लेना बहुत ही खतरनाक संकेत है। रूस अपने को परास्त होता देख अपने सम्मान और हनक की खातिर परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने से कभी नहीं चूकेगा और यदि ऐसा हुआ तो मानव जाति का महाविनाश हो सकता है। रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच इस क्षेत्र को लेकर काफी तनाव बना हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ने इस क्रीमिया क्षेत्र को तोहफे के रूप में यूक्रेन को सौंपा था। साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करते हुए रूस और यूक्रेन में शांति समझौता करवाया था। यूक्रेन और रूस में समझौते के बाद यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अच्छे बनाने में जुट गया, यह रूस की मर्जी क विरुद्ध था। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन के संबंध किसी भी पश्चिमी देश का अच्छे हों, यूक्रेन चाहता था कि वह नाटो देशों के समूह में शामिल हो। यूक्रेन रूस से सटा देश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि नाटो की सेना की आमद उसकी सीमा तक हो जाए। यूक्रेन के न मानने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध का निर्णय लेना पड़ा।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही नहीं, पूरी दुनिया मान रही थी कि रूस का मुकाबला यूक्रेन के लिए संभव नहीं, किंतु यूक्रेन भारी नुकसान के बाद भी युद्ध का मुकाबला करता रहा। शुरुआत में उसका कुछ भाग रूस के कब्जे में चला गया। रूस-यूक्रेन का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन के आम लोगों पर पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि युद्ध यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है। इस युद्ध के चलते एक अनुमान के अनुसार यूक्रेन में 8000 से अधिक आम लोगों की मौत हो चुकी है। 80 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया जबकि करीब 1.4 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस युद्ध में अब तक रूस के एक लाख 45 हजार से अधिक सैनिकों की मौत हो चुकी है, वहीं यूक्रेन को भी अपने एक लाख सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा है। युद्ध के चलते यूक्रेन में करीब 138 अरब डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के 1100 से ज्यादा अस्पताल और 1,49,300 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ओलेग उस्तेंको के मुताबिक, यूक्रेन को युद्ध की वजह से एक ट्रिलियन डॉलर (करीब आठ लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ रूस अब तक युद्ध में करीब 8,000 अरब रुपये फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन की मदद के नाम पर युद्ध में 12,520 अरब रुपये झोंक चुके हैं। भोजन और ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, महंगाई और बेरोजगारी जैसे

जुलाई महीने की शुरुआत से ही रूस आक्रामक है। पुतिन मानो खुद फ्रंटफुट पर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। रूस खुद को काला सागर अनाज समझौते से अलग कर चुका है। रूस 17 मई को इस समझौते को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुआ था। इस डील के एक हिस्से की वजह से रूस असंतुष्ट था और जुलाई में आखिरकार उसने इसके खत्म करने का ऐलान कर दिया। उधर यूक्रेन ने घोषणा कर दी कि वह रूस के बंदरगाहों से दूसरे देशों को हो रही तेल की आपूर्ति नहीं होने देगा।

कारकों को शामिल कर देखा जाए, तो युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर करीब 24 लाख करोड़ रुपये (तीन ट्रिलियन डॉलर) का बोझ पड़ा है।

नाटो देश इस युद्ध में सीधे तो शामिल नहीं हुए किंतु वह यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। यूक्रेन का उत्साह बढ़ाने को अमेरिका सहित कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन का दौरा भी किया। यूक्रेन को युद्ध में प्रत्येक प्रकार की सैन्य सहायता का वायदा नहीं किया अपितु सैन्य अस्त्र-शस्त्रों की आपूर्ति बढ़ाई। इन्हीं अस्त्र-शस्त्रों के बल पर यूक्रेन रूस के आगे टिका है। हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम सौंप दिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया तो वह भी इसका कड़ा जवाब देंगे। दरअसल क्लस्टर बम एक बेहद खतरनाक हथियार है। यह कई सारे छोटे-छोटे बमों का समूह होता है, जिन्हें एक खोल के अंदर रखा जाता है। इस बम को जमीन या हवा दोनों जगह से दागा जा सकता है। इस बम का प्रयोग किसी बड़े क्षेत्र को एक साथ खत्म करने के लिए किया जाता है। जब क्लस्टर बम को दागा जाता है तो यह जमीन पर पहुँचने से पहले ही खुल जाता है। इसके बाद इसके अंदर मौजूद बम अलग-अलग जगह बिखरकर उस पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। क्लस्टर बम को जब दागा जाता है तो इसमें मौजूद छोटे बमों में से 10 से 40 फीसदी बम फटते ही नहीं हैं। यह मिट्टी के नीचे दबे होते हैं। ऐसे में जब सालों बाद कोई आम आदमी उस जगह पर पहुंचता है तो इसकी चपेट में आ जाता है। अर्थात इन बमों से सालों तक तबाही होती रहती है।

साल 2008 में दुनिया के 120 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में क्लस्टर बम पर बैन लगाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं। हालांकि अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने अब तक क्लस्टर बम पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जहां यूक्रेन को नाटो देश सैन्य साजो-सामान और अन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने का अपराधी घोषित किया हुआ है। ऐसी हालात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का झल्लाना स्वाभाविक है। इसी झल्लाहट में वह कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। हाल में पुतिन के स्पेशल एडवाइजर और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरह जवाबी हमले करता रहा और उसने नाटो के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमें मजबूरी में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एटमी हमले की धमकी पहली बार नहीं दी गई है। फरवरी और अप्रैल में खुद पुतिन कह चुके हैं कि अगर अमेरिका और नाटो यूक्रेन की मदद करते रहे तो रूस एटमी हथियारों समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं उसने अपने परमाणु शस्त्र तैनात भी कर दिए हैं।

मेदवेदेव ने कहा है कि जरा सोचिए, अगर हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा तो क्या होगा। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की तरफ से खुली मदद मिल रही है। अगर वो हमारी जमीन छीनने की कोशिश करते हैं या रूस के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने ही होंगे। मेदवेदेव का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि जंग अगर यूक्रेन के फेवर में जाने लगी तो रूस उस पर एटमी हमला करेगा। यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि मेदवेदेव रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मेदवेदेव ने कुछ महीने पहले अमेरिका को भी सीधी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन से जंग में रूस की हार हुई तो अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ जाएगा और इसके बाद न्यूक्लियर वॉर भी होगा। ऐसा कोई हथियार नहीं है, जो रूस के पास न हो। हमने अब तक खतरनाक हथियारों का यूज किया ही नहीं, रूस आज भी जंग को चंद दिनों में खत्म कर सकता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उधर हाल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि हमने जीत की डगर पर कदम बढ़ा दिए हैं। बहुत जल्द हमारी फौज उन इलाकों को हासिल कर लेगी, जिन पर रूस ने कब्जा किया है।

78 साल का बुजुर्ग नौंवीं कक्षा में दाखिला, तीन किमी पैदल चलकर जाते स्कूल

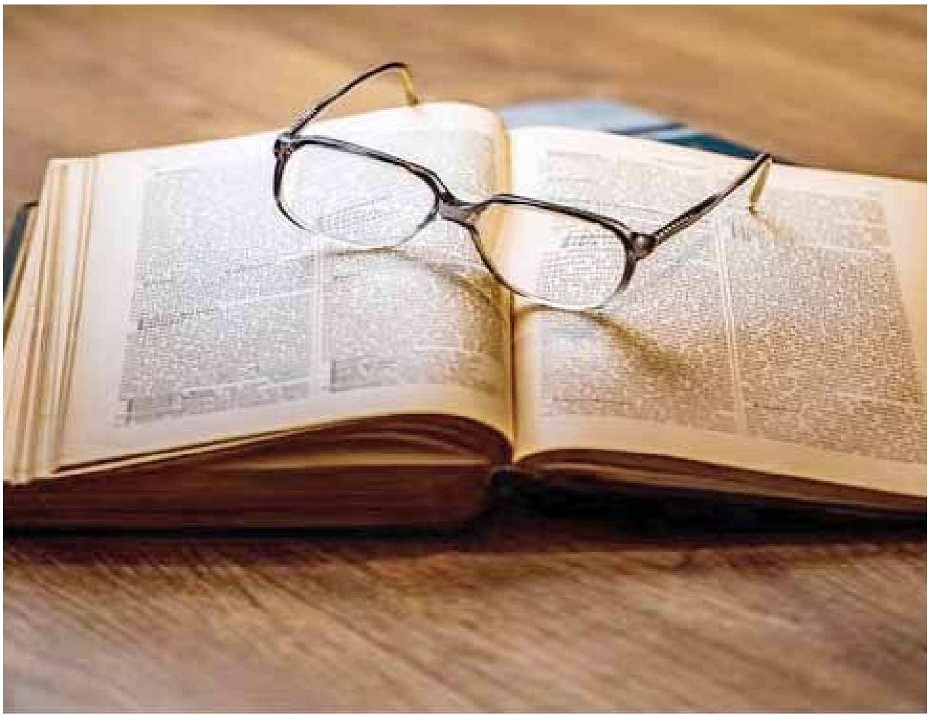

लालरिंगथारा का लक्ष्य अंग्रेजी में एप्लिकेशन लिखने और टेलीविजन समाचार रिपोर्टों को समझने में दक्षता हासिल करना था। वह मिजो भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। लालरिंगथारा कहते हैं, मुझे मिजो भाषा में पढ़ने या लिखने में कोई समस्या नहीं है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं मिजोरम के चंफाई में ह्रुआइकोन गांव के रहने वाले 78 साल के लालरिंगथारा पर। उनकी कहानी अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ह्रुआइकोन गांव में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) हाईस्कूल में नौवीं कक्षा में दाखिला लिया है। वह स्कूल यूनिफॉर्म में किताबों से भरा बैग लेकर अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए हर दिन तीन किमी की पैदल यात्रा करते हैं।

1945 में भारत-म्यांमार सीमा के पास खुआंगलेंग गांव में जन्मे लालरिंगथारा पिता की मौत के कारण कक्षा दो के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। उन्हें कम उम्र में खेतों में मां की मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह अपने माता-पिता के इकलौते बच्चे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अंत में वह 1995 में न्यू ह्रुआइकॉन गांव में बस गए। घोर गरीबी के कारण वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। वह अपनी आजीविका के लिए स्थानीय प्रेस्बिटेरियन चर्च में गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं।

ये है लक्ष्य

लालरिंगथारा का लक्ष्य अंग्रेजी में एप्लिकेशन लिखने और टेलीविजन समाचार रिपोर्टों को समझने में दक्षता हासिल करना था। वह मिजो भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। लालरिंगथारा कहते हैं, मुझे मिजो भाषा में पढ़ने या लिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा की मेरी इच्छा अंग्रेजी भाषा सीखने के मेरे जुनून से बढ़ी है। आजकल साहित्य में हर जगह कुछ अंग्रेजी शब्द शामिल होते हैं, जो अक्सर मुझे भ्रमित करते हैं। इसलिए मैंने अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए स्कूल वापस जाने का फैसला किया, ताकि अच्छी अंग्रेजी सीख सकूं।

शिक्षकों के लिए प्रेरणा भी और चुनौती भी

स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक वनलालकिमा कहते हैं कि लालरिंगथारा छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से एक प्रेरणा और चुनौती हैं, लेकिन उनका जुनून देखकर हमारे मन में भी उत्साह उमड़ पड़ता है। वनलालकिमा के मुताबिक, उन पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह नियम से स्कूल में उपस्थित होते हैं और अन्य छात्रों की तरह ही शिक्षा लेते हैं।

वायु सेना होगी और मजबूत

भारत को मिली खतरनाक इस्राइली स्पाइक NLOS; जल्द होगा परीक्षण

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में जिस पैमाने पर टैंक रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, उसे देखते हुए भारतीय वायु सेना अपने रूसी हेलिकॉप्टर बेड़े को इस्राइली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एनएलओसएएस) से लैस कर रहा है। पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना खुद को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में अपनी क्षमता तो बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को इस्राइली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट (एनएलओएस) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसके जरिए जरूरत पड़ने पर ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त किया जा सकेगा।

रक्षा सूत्रों ने इस बारे में जानकारी है। उन्होंने बताया है कि इस्राइल की खतरनाक स्पाइक एनएलओएस एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें भारत को दी जा चुकी हैं। वायुसेना जल्दी ही इसका परीक्षण भी करेगी।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में जिस पैमाने पर टैंक रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, उसे देखते हुए भारतीय वायु सेना अपने रूसी हेलिकॉप्टर बेड़े को इस्राइली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एनएलओसएएस) से लैस कर रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रूसी हेलिकॉप्टर बेड़े एमआई-17वी5 में इस्राइली एनएलओएस लगाने से यह संघर्ष की स्थिति में काफी दूर से अपने लक्ष्य को निशाना बना पाएगी और आपात स्थिति में यह काफी असरदार साबित होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों ने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका द्वारा मुहैया कराई गई टैंक रोधी मिसाइलों का बड़े प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। दरअसल, भारतीय वायु सेना ने इन मिसाइलों में दिलचस्पी लेना दो साल पहले शुरू किया, जब पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास चीन ने भारी संख्या में सैनिकों और टैंकों की तैनाती की थी। पहले टैंकों से युद्ध के लिए पश्चिमी सीमा अनुकूल मानी जाती थी, लेकिन अब यह पश्चिमी और पूर्वी सीमा दोनों में अहम भूमिका निभा सकती है।

आखिर कैसी आजादी के पक्षधर हैं हम..?

आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक पहलू पर देश में कमजोर तबके का स्तर सुधारने की नीयत से लागू आरक्षण के राजनीतिक रूप ने देश को आज उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां समूचा राष्ट्र रह-रहकर जातीय संघर्ष के बीच उलझता दिखाई देता है। 15 अगस्त का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का दिन है क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के प्रत्येक नागरिक के दिलोदिमाग में एक अलग ही जज्बा और उत्साह समाहित रहता है। हालांकि वर्षों की गुलामी के बाद गुलामी की इन जंजीरों से मिली आजादी को हम किस रूप में संजोकर रख पा रहे हैं, वह सभी के समक्ष है। देश को आजाद हुए पूरे 76 बरस हो चुके हैं लेकिन आजादी के इन 76 वर्षों में लोकतंत्र के पवित्र स्थल संसद और विधानसभाओं के हालात साल दर साल किस कदर बदले हैं, वह भी किसी से छिपा नहीं है, जहां अभद्रता की सीमा पार करते जनप्रतिनिधि अभद्रता की हर हद पार करते नजर आते हैं। प्रतिवर्ष जब देश की स्वतंत्रता के साथ-साथ राष्ट्र की आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगे के नीचे खड़े होकर बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी देश की रक्षा व प्रगति का संकल्प लेते देखते हैं, जो वर्षभर सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी संकल्प अदायगी से देश को हासिल क्या होता है? आजादी के दीवानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश को आजाद कराने के लिए वे इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, आजादी की उसकी तस्वीर ऐसी हो जाएगी।

हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए और विकास के अनेक सोपान तय किए हैं। तकनीकी कौशल हासिल करते हुए देश अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है लेकिन महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाएं जिस प्रकार लगातार बढ़ रही हैं और समाज में अपराधों की तादाद भी बढ़ रही है, ऐसे में देश की गुलामी का दौर देख चुके कुछ बुजुर्ग तो अब कहते सुने भी जाते हैं कि गुलामी के दिन आज की इस आजादी से कहीं बेहतर थे, जहां अपराधों को लेकर मन में भय व्याप्त रहता था किन्तु कड़े कानून बना दिए जाने के बावजूद अपराधियों के मन में अब किसी तरह का भय नहीं दिखता। देश के कोने-कोने से सामने आते अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बढ़ते मामले आजादी की बेहद शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। देश में महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, मध्यम वर्ग के लिए जीवनयापन दिनों-दिन मुश्किल होता जा रहा है, आतंकवाद की घटनाएं पग पसार रही हैं, आरक्षण की आग रह-रहकर देश को जलाती रहती है। ऐसे हालात निश्चित तौर पर देश के विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। हर कोई सत्ता के इर्द-गिर्द ही अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकता नजर आ रहा है, कहीं कोई सत्ता बचाने में लगा है तो कहीं कोई इसे गिराने के प्रयासों में। संसद और विधानसभाओं में हंगामेदार तस्वीरें तो अब कोई नई बात नहीं रह गई है।

आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक पहलू पर देश में कमजोर तबके का स्तर सुधारने की नीयत से लागू आरक्षण के राजनीतिक रूप ने देश को आज उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां समूचा राष्ट्र रह-रहकर जातीय संघर्ष के बीच उलझता दिखाई देता है। स्वार्थपूर्ण राजनीति ने माहौल को इस कदर विकृत कर दिया है, जहां से निकल पाना संभव ही नहीं दिखता। आजादी के बाद के इन साढ़े सात दशकों में महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। भले ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसे जाने के कितने ही ढ़ोल क्यों न पीटे जाते रहें किन्तु वास्तविकता यही है कि आज भी अधिकांश जगहों पर बिना लेन-देन के कार्य सम्पन्न नहीं होते। बड़े नेताओं की तो छोड़ दें, छुटभैया नेताओं की भी चांदी हो चली है। आजादी के बाद लोकतंत्र के इस बदलते स्वरूप ने आजादी की मूल भावना को बुरी तरह तहस-नहस कर डाला है।

आजादी का एक शर्मनाक पहलू यह भी है कि गिने-चुने मामलों को छोड़कर हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से विभूषित जनप्रतिनिधि भी प्रायः सम्मानित जिंदगी जीते रहते हैं। देश के ये बदले हालात आजादी के कौनसे स्वरूप को उजागर कर रहे हैं, विचारणीय है। लोकतंत्र के हाशिये पर खड़ी देश की जनता के लिए इस दिशा में फिर से चिंतन-मंथन करना आवश्यक हो गया है कि वह आखिर किस तरह की आजादी की पक्षधर है? आज की आजादी, जहां तन के साथ-साथ मन भी आजाद है, सब कुछ करने के लिए, चाहे वह वतन के लिए अहितकारी ही क्यों न हो, या उस तरह की आजादी, जहां वतन के लिए अहितकारी हर कदम पर बंदिश हो। आज की आजादी, जहां स्वहित राष्ट्रहित से सर्वोपरि होकर देशप्रेम की भावना को लीलता जा रहा है, या वह आजादी, जहां राष्ट्रहित की भावना सर्वोपरि स्वरूप धारण करते हुए देश को आजाद कराने में गुमनाम लाखों शहीदों के मन में उपजे देशप्रेम का जज्बा सभी में फिर से जागृत कर सके।

सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार बना रही योजना

सेना के मेडिकल कैडर में 1 जुलाई, 2023 तक महिलाओं की कुल संख्या आर्मी मेडिकल कोर में 1,212 है, आर्मी डेंटल कोर में 168, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 3,841 है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 तक भारतीय सेना (एएमसी, एडीसी और एमएनएस को छोड़कर) में महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1,733 है। भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि जुलाई 2022 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में प्रति वर्ष महिला कैडेटों के लिए 20 रिक्तियां आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाओं के लिए 90 रिक्तियां हैं, जिसमें जून 2023 से 10 अतिरिक्त रिक्तियां भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया, मार्च 2023 से आर्टिलरी इकाइयों के साथ-साथ रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर में भी महिला अधिकारियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एविएशन में पायलट के रूप में महिला अधिकारियों का प्रवेश जून 2021 से शुरू हुआ।

महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1700 के पार : सेना के मेडिकल कैडर में 1 जुलाई, 2023 तक महिलाओं की कुल संख्या आर्मी मेडिकल कोर में 1,212 है, आर्मी डेंटल कोर में 168, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 3,841 है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 तक भारतीय सेना (एएमसी, एडीसी और एमएनएस को छोड़कर) में महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1,733 है।

कोई रक्षा ऑफसेट दायित्व पिछले पांच वर्षों में नहीं हुआ समाप्त : रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी ऑफसेट दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि रक्षा ऑफसेट दायित्वों की कीमत 6.85 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं। भारत की ऑफसेट नीति के तहत, 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सभी अनुबंधों के लिए विदेशी रक्षा संस्थाओं को कलपुर्जों की खरीद, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अनुसंधान की स्थापना के माध्यम से भारत में कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य है। हालांकि ऑफसेट 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के तहत खरीद पर और 'विकल्प खंड' मामलों में लागू नहीं होते हैं, यदि मूल अनुबंध में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अलावा, अंतर-सरकारी समझौतों के तहत अनुबंधों में कोई ऑफसेट लागू नहीं होता है। सभी ऑफसेट अनुबंधों का कुल मूल्य 13.21 अरब अमेरिकी डॉलर है।

डिफॉल्ट होने पर दंडात्मक कार्रवाईः भट्ट ने कहा कि लागू रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार डिफॉल्ट विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा, मौजूदा रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों में ऑफसेट की गुणवत्ता का आकलन बोली मूल्यांकन मानदंड के रूप में प्रदान नहीं किया गया है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में 8,630 करोड़ जमा

वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (एमएसएससी) के तहत 14.83 लाख खाते खोले गए। इसमें 8,630 करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सरकार की एक नई शुरू की गई लघु बचत योजना है और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए है।

कोविड के दो साल बाद तक मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित

हमारे प्रतिभागियों में ज्यादातर महिलाएं थीं, और ब्रिटेन की सामान्य आबादी की तुलना में श्वेत पृष्ठभूमि से आने वाले और अधिक समृद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक था। बहरहाल, हमारा अध्ययन उन लोगों की निगरानी करने और उनके सामान्य होने में सहायता करने की आवश्यकता को दर्शाता है जिनके मस्तिष्क का कार्य कोविड से सबसे अधिक प्रभावित होता है।

संज्ञानात्मक कार्यों या कौशलों, जैसे पुरानी बातों को याद करने की क्षमता, कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, या बातचीत में सही शब्द ढूंढने में आने वाली कठिनाइयां, आमतौर पर कोविड संक्रमण के बाद बताई जाती हैं। इन लक्षणों को अक्सर ब्रेन फ़ॉग के रूप में संदर्भित किया जाता है, और विशेष रूप से उन लोगों में आम है जिनमें दीर्घकालिक या लगातार लक्षण होते हैं जिन्हें लॉन्ग कोविड कहा जाता है। मार्च 2023 की नवीनतम गणना के अनुसार, यूके में लंबे समय तक कोविड से पीड़ित 10 लाख लोग थे जिन्होंने ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की सूचना दी थी, और तकरीबन साढ़े सात लाख लोगों ने स्मृति हानि या भ्रम की सूचना दी थी। अल्पावधि में, ब्रेन फ़ॉग के लक्षण लोगों की उनके सामान्य दैनिक कार्यों, जैसे कामकाज और बच्चे की देखभाल, को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।

लंबी अवधि में, हल्की संज्ञानात्मक हानि मनोभ्रंश जैसी अधिक गंभीर स्थितियों में विकसित हो सकती है। आम तौर पर कोविड संक्रमण को मनोभ्रंश के निदान के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। इसलिए छोटी और लंबी अवधि में लोगों की सहायता करने के लिए, आमतौर पर संज्ञानात्मक कार्य पर ब्रेन फॉग और लंबे कोविड के प्रभावों की प्रकृति, आकार और अवधि को समझना महत्वपूर्ण है। एक नए अध्ययन में, मैं और मेरे सहकर्मी यह समझने के लिए निकले कि क्या कोविड संक्रमण, और लक्षण अवधि, संज्ञानात्मक परीक्षणों में प्रदर्शन को प्रभावित करती है, और समय के साथ परीक्षण प्रदर्शन कैसे बदल गया है। हमने पाया कि लगातार लक्षण वाले लोगों की स्थिति कोविड संक्रमण के दो साल बाद तक इन परीक्षणों में बदतर रही। दिमागी प्रशिक्षण संज्ञानात्मक कौशल का परीक्षण करने के लिए, हमने जुलाई 2021 में और फिर अप्रैल 2022 में 12 मस्तिष्क-प्रशिक्षण-शैली कार्यों की एक श्रृंखला को ऑनलाइन पूरा करने के लिए कोविड लक्षण अध्ययन बायोबैंक में प्रतिभागियों को आमंत्रित किया। पहले दौर में, 3,300 से अधिक लोगों ने परीक्षण पूरा किया।

अन्य 2,400 ने दूसरा दौर पूरा किया, जिनमें से 1,700 ने पहले दौर में भी भाग लिया था। कोविड लक्षण अध्ययन बायोबैंक एक अध्ययन है जो 2020 में शुरू हुआ, जिसमें कोविड लक्षण अध्ययन स्मार्टफोन ऐप (अब जैडओई हेल्थ स्टडी) से लोगों को भर्ती किया गया जो लक्षणों और कोविड परीक्षणों को ट्रैक करता है। अध्ययन में 8,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया है, जिनके पास पहले से ही कोविड संक्रमण का इतिहास था और जिनके पास कम और लंबी अवधि के कोविड लक्षण थे।

राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं- मंत्री गडकरी

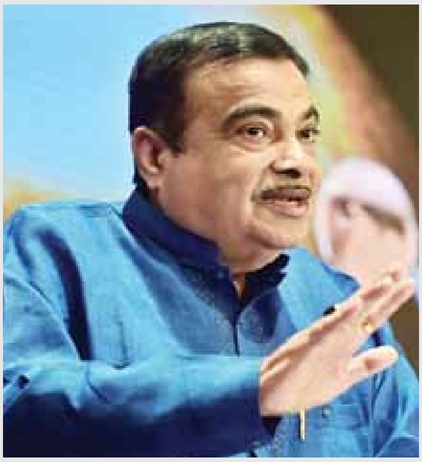

गडकरी ने कहा कि वह अपना भाषण हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में देते हैं और आज लोग यूट्यूब पर उनका भाषण सुनते हैं। अमेरिका में उनके भाषण सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं और उससे वे यूट्यूब से हर महीने 3 लाख रुपए कमाते हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि देश में एक भी व्यक्ति अगर यह कहे कि उसने कमीशन के रूप में एक पैसा भी लिया तो भाजपा नेता राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि गडकरी को एक भी पैसा दिया गया है, राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। गडकरी ने कहा कि वह अपना भाषण हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में देते हैं और आज लोग यूट्यूब पर उनका भाषण सुनते हैं। अमेरिका में उनके भाषण सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं और उससे वे यूट्यूब से हर महीने 3 लाख रुपए कमाते हैं।

गडकरी ने कहा कि उन्हें खुलकर बोलने में कोई झिझक नहीं होती। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह नौकरी नहीं करेंगे बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। उनके माता-पिता ने उन्हें वकील बनने के लिए कहा लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वह नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जाति, धर्म और भाषा से लोग महान नहीं बनते, लोग अपने कर्म और गुणों से महान बनते हैं। गडकरी ने कहा कि वह जाति की बात नहीं करते, वह नेता हैं, उन्हें हर जाति का वोट चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो भी जाति के बारे में बात करेगा उसे जोरदार लात मारी जाएगी।

सभी जाति के लोग मेरे भाई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी जाति के लोग मेरे भाई हैं, मेरा परिवार हैं। मैं इस बात को समझता हूं। आज वह कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जो बिजनेस किया है, उसका टर्नओवर ढाई हजार करोड़ का है। उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है, उसमें उन्होंने 15,000 लोगों को नौकरी दी है और उनमें से 200 लोग भी उनकी जाति के नहीं हैं। इससे पहले केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सजग है और देश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के बाद सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने के संबंध में सड़क सुरक्षा ऑडिट कराके उपाय निकाले जाएंगे।

एक वर्ष में 1 लाख सरकारी पदों पर की जाएगी भर्ती

अभी तक 60 हजार पदों पर नियुक्ति : सीएम

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक वर्ष में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होंगी, जिसमें से लगभग 60 हजार पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रदेश की जनता मेरा परिवार है और मैं सरकार को परिवार की तरह ही चलाने का प्रयास करता हूँ। गरीब और मजदूर हमारे लिए भगवान हैं। शासकीय सेवा में आपका चयन उनकी सेवा के लिए हुआ है। गरीब और मजदूर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें काम का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आबकारी, श्रम और सहकारिता विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय पर कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए और शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछली 15 अगस्त पर मैंने एक साल में एक लाख पदों पर भर्ती की बात कही थी। यह भर्ती अभियान निरंतर जारी है। अब तक 60 हजार लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है। आज की नियुक्तियां भी इसमें शामिल हैं। हमारी प्रतिबद्धता रही है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में भर्तियां हों। आप सबका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है, अतः आप सब बधाई के पात्र हैं। शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आपके माध्यम से ही होगा। आप इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करें, यही आशीर्वाद और शुभकामनाएँ हैं। 'मेरी अपेक्षा है कि आप इस भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें कि हम केवल अपने लिए नहीं, अपितु प्रदेश की जनता और प्रदेश के लिए हैं। शासकीय सेवा का अर्थ है, जनता की सेवा और प्रदेश एवं देश का विकास। इसके लिए कर्तव्य और दायित्व का भाव सदैव मन में रहना चाहिए। आप पर ही प्रदेश की प्रगति और विकास निर्भर है। आप पर ही जन-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन भी निर्भर है'।

प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश, विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2002-03 में 11 हजार रूपए हुआ करती थी, अब बढ़कर एक लाख 40 हजार रूपए हो गई है। जीएसडीपी 15 लाख करोड़ और प्रदेश का बजट 3 लाख 15 हजार करोड़ का है। सड़क, पानी, बिजली सहित संपूर्ण अधोसंरचना के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। साथ ही सामाजिक सरोकार रखने वाले विभागों में भी संवेदनशीलता के साथ गतिविधियाँ संचालित हैं।

कुल 741 को नियुक्ति पत्र वितरित

कार्यक्रम में कुल 741 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए गए। आबकारी विभाग में 340 आबकारी आरक्षकों, सहकारिता विभाग में 347 क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर तथा श्रम विभाग में बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक ग्रेड 3 और सफाई सेवक के पदों पर कुल 54 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आबकारी आयुक्त श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी तथा चयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण हैं सहकारिता, श्रम और आबकारी के दायित्व

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहकारिता विभाग सामाजिक सरोकार से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराकर लोगों के और प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। श्रम विभाग श्रमिकों को काम का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेषकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण नहीं हो, इस दृष्टि से सतर्क रहना आवश्यक है। आबकारी विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है। नशे पर नियंत्रण और अवैध शराब की बिक्री न हो, इसके लिए सदैव चौकन्ना रहना विभाग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। इस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी संकल्प लें कि अवैध गतिविधियों को संचालित नहीं होने देंगे और राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। नई आबकारी नीति में अहाते बंद करने का निर्णय लेकर उसका सफल क्रियान्वयन किया गया है। नशे पर नियंत्रण के लिए लोगों की मानसिकता में सुधार और जन-जागरूकता का कार्य भी करना होगा।

जनता भाजपा को एकतरफा आशीर्वाद देगी : जेपी नड्डा

बैठक में कोर कमेटी के सदस्य राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी नितिन पटेल, प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, सांसद कनकमल कटारा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को विश्वास जताया कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता पार्टी को एकतरफा आशीर्वाद को देगी। साथ ही नड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम में फेरबदल समय को ध्यान में रखते हुए किया है। वहीं राज्य की राजनीति में हंगामा मचाने वाली कथित लाल डायरी के बारे में उन्होंने कहा, ''पाप का घड़ा भरता है तो वह इस तरह से उजागर होता है।'' उन्होंने यहां मीडिया से कहा, ''मैं आश्वस्त हूं कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता भाजपा को एकतरफा आशीर्वाद देने वाली है। इसके साथ-साथ 2024 में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।''

राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। नड्डा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से कहा, ''सही मायने में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जैसी स्थिति हमें दिख रही है, उसके तहत एक तारीख को पार्टी का 'नहीं सहेगा राजस्थान' अभियान सफल होगा।'' उन्होंने कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहां लूट मची हुई और राज्य का किसान बेहाल व ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हाल ही में चर्चा में आई कथित लाल डायरी का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा, ''यह गहलोत सरकार नहीं यह गृह लूट सरकार है। यह घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो (के सिद्धांत वाली है)। हर जगह भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है...पाप का घड़ा भरता है तो वह इस तरह से उजागर होता है।

भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से हम सबको देखने को मिल रहा है।'' नड्डा ने कहा, ''जिस तरह का मैं वातावरण देख रहा हूं... प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) की नीतियों के कारण, साधारण व्यक्ति का जो सशक्तिकरण हुआ है... गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, हमारी माताएं बहनें... इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भलीभांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि वह आने वाले समय में भाजपा को पूरा आशीर्वाद देकर सफल बनाएगी।'' अपनी नई टीम के बारे में नड्डा ने कहा, ''हमारी टीम हमेशा समय को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं और हमने फैसला किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए हमें टीम को भी रद्दोबदल करने की आवश्यकता थी। इसमें हम जीत हासिल करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''वर्तमान में हमारे कई लोकसभा सदस्य पार्टी के पदाधिकारी भी थे।

चूंकि वे चुनाव सही से लड़ सकें ऐसे में उन्हें समय देना और नये लोगों को मौका देना भी जरूरी था। हम संगठन को लेकर लचीले हैं और नये लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और हमारे यहां यह सतत चलता रहता है।'' नड्डा ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय टीम में फेरबदल करते हुए कर्नाटक के सी टी रवि और असम से लोकसभा सदस्य दिलीप सैकिया की राष्ट्रीय महासचिव पद से और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह की उपाध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी। पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी बैठक आयोजित हुई जिसमें पार्टी की आगामी योजनाओं और चुनावी रणनीति को लेकर बारीकी से मंथन किया गया।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने लगातार 10वीं बार फहराया तिरंगा..

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लाल किले पर पहुंचने और तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे और उन्होंने यहां बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया है। ये लगातार 10वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की ऐतिहासिक प्राचीर से तिरंगा फहराया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लगातार 10 बार यूपीए के कार्यकाल में तिरंगा फहराया था।

लाल किले पर तिरंगा फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर काफी चर्चा है, जिसे सुनने के लिए पूरा देश आतुर है। इससे पहले उन्होंने लाल किले पर पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। लाल किले पर पहुंचने और तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे थे और उन्होंने यहां बापू महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले, लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लाल किला पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायु सेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क-III ध्रुव ने कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

भारत का बंटवारा इतिहास का सबसे पीड़ा दायक और दर्दनाक घटना : भाजपा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान में कहा है कि विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम भाजपा का अपने पूर्वजों के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए है। शुक्ला ने कहा है कि भारत विभाजन के गुनहगार हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक ताकतें थी, जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति में सहयोग करती रही।

छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि 14 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हमारे इतिहास का सबसे पीड़ा दायक और दर्दनाक घटना थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनों को खोया। भाजपा नेताओं ने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 'मेरा माटी, मेरा देश' के तहत बिलासपुर जिले के बिल्हा कस्बे में आयोजित तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 14 अगस्त 1947 के विभाजन को याद करते हुए 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाया गया तथा विभाजन की विभीषिका झेलकर बलिदान देने वाले लाखों निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजली दी गयी।

इस अवसर कौशिक ने कहा कि 14 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हमारे इतिहास का सबसे पीड़ा दायक और दर्दनाक घटना थी। इस विभाजन के कारण लाखों लोगों ने अपनों को खोया, क्रूरता और विस्थापन की विभीषिका को झेला। कौशिक ने कहा कि देश के बंटवारे की विभीषिका ने लाखों परिवारों को अपनी जन्मभूमि से अलग कर दिया। इस त्रासदी की स्मृतियां आज भी असंख्य लोगों के लिए बुरे स्वप्न से कम नहीं हैं। वहीं रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा विभाजन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। दिवस का उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभीषिका के दौरान लोगों द्वारा सही गई वेदना और यातना का स्मरण कराना है।

सीएम शिवराज ने भोपाल के लाल परेड मैदान में फहराया तिरंगा...

मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जाएगी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार परेड में 18 टुकड़ियां शामिल हो रही है, हर्ष फायर किया गया। पहली बार लाड़ली बहना सेना भी परेड में शामिल हुई । इसके पहले सीएम शिवराज ने अपने निवास पर भी ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे वंचितों को आवास उपलब्ध कराएं जाएंगे।मुख्यमंत्री मेघावी योजना प्रारंभ कर रहे है।

जिससे हमारे बच्चों को लाभ मिले। महालोक की तर्ज पर प्रदेश के कई स्थानों पर धार्मिक लोग बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार अश्वारोही दल भी शामिल किया गया है। हर वर्ष यह आयोजन मोती लाल नेहरू स्टेडियम में होता था, पर इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम लाल परेड मैदान में हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां उत्कृष्ट सेवा और वीरता के लिए पदक पाने वाले पुलिस के 66 अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे।

स्वतंत्रता दिवस परेड की कमांडर डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना की बेटी सोनाक्षी सक्सेना है। वह 2020 बैच की आइपीएस अधिकारी हैं। अभी इंदौर में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को परेड की सलामी दी। सहायक परेड कमांडर डीएसपी राहुल सैय्याम है।

20 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक और चार को वीरता पुलिस पदक मिलेगा : मध्य प्रदेश पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ चार अधिकारी व कर्मचारियों को वीरता पदक एवं 20 अधिकारी-कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। पदकों का वितरण अगले साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए पुलिस का वीरता पदक एएसपी आदित्य मिश्रा, उप निरीक्षक रामपदम शर्मा, सहायक उप निरीक्षक आशीष शर्मा तथा आरक्षक रमेश विश्वकर्मा को देने की घोषणा की गई है।राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक एडीजी आशुतोष राय, एडीजी/ओएसडी ए.साईं मनोहर, पुलिस उपायुक्त मनीष कपूरिया एवं इंदौर के निरीक्षक अशोक कुमार रघुवंशी को दिया जाएगा। सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एआइजी मलय जैन, एएसपी सुरेन्द्र कुमार जैन, डीआइजी मनोज कुमार श्रीवास्तव, एसपी ग्वालियर (अजाक) पंकज कुमार पांडे, भोपाल पुलिस अधीक्षक (एटीएस) प्रणय नागवंशी, ग्वालियर एसपी (लोकायुक्त) रामेश्वर सिंह यादव, डीजीपी के स्टाफ आफिसर (एएसपी) संदेश जैन, उज्जैन डीएसपी अजय कैथवास, निरीक्षक सुनील कुमार राय, उप निरीक्षक डीपी सक्सेना, इंदौर के आरक्षक मोहनलाल, छिंदवाड़ा के प्रधान आरक्षक केशव राव इंगले, ग्वालियर के प्रधान आरक्षक अशोक सिंह भदौरिया, उज्जैन के प्रधान आरक्षक राम रतन नादेड़, सागर के आरक्षक रमेश जोशी और उज्जैन के डीएसपी सुनील कुमार तालान को दिया जाएगा।

संसदीय समिति का सुझाव

18 वर्ष हो लोकसभा और विस चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र

भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कानून और कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा ने कहा कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की प्रथाओं की जांच करने के बाद, समिति का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

एक संसदीय पैनल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम करने की वकालत करते हुए तर्क दिया है कि इससे युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। वर्तमान ढांचे में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद के लिए चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार मिलता है। पैनल ने शुक्रवार (4 अगस्त) को लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु मौजूदा 25 साल से घटाकर 18 साल करने की सिफारिश की।

भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कानून और कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा ने कहा कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की प्रथाओं की जांच करने के बाद, समिति का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इन देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि युवा व्यक्ति विश्वसनीय और जिम्मेदार राजनीतिक भागीदार हो सकते हैं। इसने 'विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने' का भी सुझाव दिया। पैनल ने आगे तर्क दिया कि यह कदम युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह दृष्टिकोण वैश्विक प्रथाओं, युवा लोगों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना और युवा प्रतिनिधित्व के फायदों जैसे बड़ी मात्रा में सबूतों से पुष्ट होता है।' चुनाव आयोग के अनुसार, जब तक संविधान के किसी प्रावधान को बदलने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, इसे अपरिवर्तित रहना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग और सरकार को युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि फ़िनलैंड की नागरिकता शिक्षा जैसे अन्य देशों के सफल मॉडलों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें तदनुसार अपना सकते हैं।

राजनाथ सिंह बोले- चाहे कोई खेल हो या देश हो, सच्चा खिलाड़ी और नागरिक वहीं होता है जो...

भाजपा नेता ने कहा कि फुटबॉल, लोगों को जोड़ने वाला खेल है; यह शांति का खेल है। यह सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि गेम से कहीं अधिक बढ़कर है। उन्होंने कहा कि असम ने भी हाल के दिनों में खेलों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 'डूरंड कप 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल हो या समाज हो या देश हो, उसमें नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चा खिलाड़ी और सच्चा नागरिक वही है जो खेल और समाज के नियमों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाए। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कई लोगों से यह सुन रखा था,

कि भारत का पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र, फुटबॉल के प्रति अपने उत्साह के लिए जाना जाता है। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने में यह जो दृश्य देख रहा हूँ, डूरंड कप को लेकर आप लोगों के अंदर जो उत्साह देख रहा हूँ; उसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया है, कि नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के दिलों का रास्ता फुटबॉल से होकर जाता है। राजनाथ ने कहा कि फुटबॉल जिसे पूरी दुनिया मेंसुन्दर खेल के नाम से जाना जाता है, यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक भावना भी है। आप लोगों ने महान ब्राज़ीली फुटबॉलर पेले का नाम तो सुना ही होगा। उनसे सम्बंधित एक घटना बड़ा ही चर्चित है। मुझे वह घटना याद आ रहा है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में नाइजीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था।

सत्य की हमेशा जीत होती है

मैं समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद देता हूं: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गांधी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गांधी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है। मुझे क्या करना है, उसे लेकर मेरे मन में स्पष्टता है।'' उन्होंने लोगों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे।

उन्होंने ट्वीट किया, ''चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत की अवधारणा की रक्षा करना।'' उच्चतम न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।

शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में 'मोदी उपनाम' के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

पिछले 5 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ: मल्लिकार्जुन खरगे

खरगे ने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में पिछले पांच वर्षों में संगठित क्षेत्र की केवल 12.2 लाख नई नौकरियां सृजित की गईं। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ष औसतन केवल 2,44,000 नौकरियां मिलीं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ। उन्होंने यह दावा भी किया कि भाजपा के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। खरगे ने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में पिछले पांच वर्षों में संगठित क्षेत्र की केवल 12.2 लाख नई नौकरियां सृजित की गईं। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ष औसतन केवल 2,44,000 नौकरियां मिलीं। हम इस आंकड़े को पेश नहीं कर रहे हैं। यह

मोदी सरकार ही है जिसने यह विमर्श गढ़ा कि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में नियमित खाताधारकों की संख्या का मतलब उतनी नौकरियों का सृजन होता है! ईपीएफ डेटा इसकी पुष्टि करता है।''

उन्होंने दावा किया, ''भाजपा ने प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था! यानी 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती थीं। हमारा युवा अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सड़कों पर गुस्सा और हिंसा है। रोजगार देने में भाजपा बुरी तरह विफल!'' कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अकल्पनीय स्तर की बेरोजगारी, पीड़ादायक महंगाई और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण यह विनाशकारी स्थिति पैदा हुई है। खरगे ने कहा, ''हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के अस्तित्व के लिए, भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा।

ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वैरिएंट

बुजुर्ग अस्पतालों में हो रहे भर्ती

कोरोना वायरस ने देश-दुनिया में काफी कहर बरपाया है, न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी इस वायरल ने लील ली। लेकिन एक चिंता की खबर ब्रिटेन से आई हैं, यहां पिछले महीने कोविड का एक नया स्वरूप ईजी.5.1 सामने आया था जो अब तेजी से देश में फैल रहा है। इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह वैरिएंट ओमिक्रॉन से आया है। इसे ईजी.5.1 एरिस उपनाम दिया गया है और यह सात नए कोविडमामलों में से एक है।

लोग टीकों से बेहतर सुरक्षित हैं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर एशिया में बढ़ते मामलों के कारण देश में इसकी व्यापकता दर्ज होने के बाद 31 जुलाई को इसे कोविड के एक स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दो हफ्ते पहले ही ईजी.5.1 स्वरूप पर उस वक्त नजर रखना शुरू कर दिया था जब डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा था कि लोग टीकों और पूर्व संक्रमण से बेहतर सुरक्षित हैं, लेकिन देशों को अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देनी चाहिए।

नया स्वरूप अधिक गंभीर है?

इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नया स्वरूप अधिक गंभीर है क्योंकि यूकेएचएसए के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि यह अब देश के सभी कोविड मामलों का 14.6 फीसदी है। यूकेएचएसए के 'रेस्पिरेटरी डेटामार्ट सिस्टम' के माध्यम से दर्ज किये गये 4,396 नमूनों में से 5.4 फीसदी को कोविड-19 के रूप में दर्ज किया गया था। यूकेएचएसए की टीकाकरण प्रमुख डॉ मैरी रामसे ने कहा कि हम देख रहे हैं इस हफ्ते की रिपोर्ट में कोविड-19 मामलों में वृद्धि जारी है। ज्यादातर आयु समूहों में, विशेषकर बुजुर्ग बड़ी संख्या में अस्पतालों में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से हाथ धोने से आपको कोविड-19 और अन्य वायरस से बचाने में मदद मिलती है। यदि आपमें सांस की बीमारी के लक्षण हैं, तो हम जहां तक संभव हो दूसरों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

शादी के 18 साल बाद पत्नी से अलग होंगे कनाडाई पीएम

इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक पोस्ट

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर तालाक के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काफी बातचीत के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। अपने पोस्ट में पीएम ट्रूडो ने कहा कि हमेशा की तरह हम एक परिवार ही रहेंगे। कनाडा के पीएम शादी के 18 साल बाद अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं। दंपती ने इंस्टाग्राम पर अपने तालाक की पुष्टि की। हालांकि, पीएमओ का कहना है कि बच्चों की देखभाल के लिए दंपती कई मौकों पर एक साथ देखे जा सकते हैं। दंपती अपने तीनों बच्चों को एक बेहतर माहौल देना चाहते हैं।

क्या बोले पीएम ट्रूडो

कनाडाई मीडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर तालाक के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काफी बातचीत के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। अपने पोस्ट में पीएम ट्रूडो ने कहा कि हमेशा की तरह हम एक परिवार ही रहेंगे। प्रेम और आदर की भावना से हमने एक दूसरे के लिए जितना भी किया है, जो कुछ भी किया है, वह आगे भी जारी रखेंगे। पीएम के इसी पोस्ट को उनकी पत्नी सोफी ने भी अपने अकाउंट से शेयर किया।

पीएम ट्रूडो ने कनाडाई जनता से अपील की है कि वह इस समय उनके बच्चों की बेहतरी के लिए मामले में गोपनियता का सम्मान करें। बता दें, दंपती के तीन बच्चे हैं- जैवियर (15), एला-ग्रेस (14), हैदरियन (9)। वहीं, एक सोशल मीडिय पर पोस्ट पर सोफी ने स्वीकार किया कि दीर्घकालिक रिश्ते कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होते हैं।

ध्यान केंद्रित करना अहम

इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा, पीएमओ ने भी संबंध में एक बयान जारी किया है। पीएमओ ने भी पुष्टि की कि दंपती ने तालाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएमओ के प्रवक्ता एलिसन मर्फी ने कहा कि दंपती ने अलग होने के फैसले के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। पीएमओ ने कहा कि पीएम और सोफी का ध्यान फिलहाल अपने बच्चों पर ही है। वे अपने तीनों बच्चों के लिए अपने बच्चों को सुरक्षित, प्रेमपूर्ण तरीके से पालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग होने के बाद भी वे अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। पीएमओ ने कहा कि उम्मीद है कि कनाडावासियों को अकसर दंपती साथ दिखेंगे। वे अगले सप्ताह की शुरुआत में वैकेशन पर जा सकते हैं।

2005 में हुई थी शादी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम जस्टिन और सोफी ने 28 मई 2005 में शादी की थी। 2023 की शुरूआत में किंग चार्ल्स III के राज्यभिषेक में शामिल होने के लिए दंपती लंदन गए थे। इसके अलावा मार्च में दंपती ने मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन की आधिकारिक ओटावा यात्रा की मेजबानी की थी।

जब वायु सेना को भारत के ही लोगों पर बम गिराने का दे दिया गया आदेश

57 साल पहले इंदिरा गांधी के फैसले का प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र

5 मार्च, 1966, वह दिन था जब भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लड़ाकों ने उग्रवाद फैलने के जवाब में असम के तत्कालीन लुशाई हिल्स जिले में आग लगाने वाले बम बरसाए और कई शहरी समूहों को तबाह कर दिया।

पीएम मोदी ने आज अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए नॉर्थ ईस्ट की असल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने वायु सेना के माध्यम से मिज़ोरम की असहाय जनता पर हमला किया। मिज़ोरम आज भी उस भयानक दिन का शोक मनाता है। उन्होंने कभी लोगों को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की...कांग्रेस ने इस घटना को देश के लोगों से छुपाया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं।

लुशाई हिल्स पर बरसाए गए बम

5 मार्च, 1966, वह दिन था जब भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लड़ाकों ने उग्रवाद फैलने के जवाब में असम के तत्कालीन लुशाई हिल्स जिले में आग लगाने वाले बम बरसाए और कई शहरी समूहों को तबाह कर दिया। देश के अपने ही नागरिकों पर बमबारी का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), जो उस समय एक विद्रोही संगठन था। यह एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और अब मिजोरम में सरकार में है। उसने 1 मार्च, 1966 के शुरुआती घंटों में भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा के बाद, एमएनएफ विद्रोहियों ने लुशाई हिल्स (वर्तमान मिजोरम राज्य) में भारतीय सेना और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमले शुरू किए।

उग्रवाद से घिरा नागालैंड

1 मार्च, 1966 को तड़के एमएनएफ विद्रोहियों ने आइजोल में जिला खजाने और लुंगलेई और चम्फाई में पुलिस और सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला किया। इन दोनों शहरों पर एमएनएफ ने कब्जा कर लिया था। विद्रोहियों ने आइजोल में असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय पर हमला किया और 3 मार्च की रात को आइजोल (वर्तमान राज्य की राजधानी) के चानमारी इलाके में असम राइफल्स के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अर्धसैनिक बल के पांच जवानों की मौत हो गई। नागालैंड पहले से ही उग्रवाद से घिरा हुआ था और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने एमएनएफ प्रमुख लालडेंगा की योजनाओं के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट जारी किया। लालडेंगा ने पाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित किया था और वह एमएनएफ को हथियारों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा था, इसके अलावा विद्रोहियों को पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रहा था। लुशाई हिल्स पूर्वी पाकिस्तान के साथ 318 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है।

ऑपरेशन जेरिको

पांच साल के समय में (फरवरी 1966 तक) पाकिस्तानी सेना की सहायता और प्रशिक्षण के कारण एमएनएफ की ताकत आठ बटालियनों तक बढ़ गई थी। फिर एक योजना बनाई गई, जिसका कोडनेम 'ऑपरेशन जेरिको' रखा गया। इस योजना के अनुसार, एमएनएफ विद्रोही सरकारी खजाने, ईंधन स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों पर आश्चर्यजनक हमले करेंगे और भारतीय सुरक्षा बलों के शिविरों और ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। 'ऑपरेशन जेरिको' में लुशाई हिल्स में कार्यरत वरिष्ठ गैर-मिज़ो सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाना भी शामिल था। पुलिस को बेअसर करने और सेना और अर्धसैनिक ठिकानों पर कब्जा करने के बाद, एमएनएफ ने आइजोल में स्वतंत्र मिजोरम का झंडा फहराने और इसे 48 घंटों तक फहराए रखने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने लालडेंगा को आश्वासन दिया कि वह कुछ अन्य देशों के साथ इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएगा और विश्व निकाय से मिजोरम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलवाएगा। पाकिस्तान ने नए देश को तुरंत राजनयिक मान्यता देने का वादा किया। पाकिस्तान की काफी मदद से बनाई गई योजना के अनुसार, एमएनएफ विद्रोहियों ने आइजोल में सरकारी प्रतिष्ठानों और असम राइफल्स बटालियन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन असम राइफल्स के जवान आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन तीन दिनों तक डटे रहे। उनके पास गोला-बारूद की कमी हो रही थी और उन्होंने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की अपील की। 4 मार्च को ऐसा प्रतीत हुआ कि घिरा हुआ असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय विद्रोहियों के हाथ में आ जाएगा और 'ऑपरेशन जेरिको' सफल हो जाएगा। तभी गृह मंत्री नंदा और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी घबरा गए। लुशाई पहाड़ियों पर अतिरिक्त सेना भेजने में समय लगेगा क्योंकि एमएनएफ विद्रोहियों ने आइजोल की ओर जाने वाली सड़कों पर नियंत्रण कर लिया है और इन सड़कों का उपयोग करने वाले सेना या अर्धसैनिक काफिले पर घात लगाए जाने का गंभीर खतरा था।

तमामा दावों के बावजूद देश में नहीं सुधर रहे हैं

सीवर सफाई कर्मियों के हालात

कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाली एजेंसी के पास सीवर लाईन के नक्शे, उसकी गहराई से सम्बंधित आंकड़े होना चाहिए। सीवर सफाई के काम में लगे लोगों की नियमित स्वास्थ्य की जांच, नियमित प्रशिक्षण देने के नियम का पालन होता कहीं नहीं दिखता है।

देश में सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों केन्द्र व सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि यदि सफाईकर्मी अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को उसे 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी भी किए। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और इसके अलावा उच्च न्यायालयों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए। कोर्ट का यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया है।

प्रतिबंध के बावजूद आज भी भारत में गंदी नालियों और सेप्टिक टैंकों की सफाई इंसानों द्वारा हाथों से की जाती है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले पांच सालों में इस तरह की सफाई करने के दौरान 347 लोगों की मौत हो गई। लोक सभा में सामाजिक न्याय मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने माना है कि भारत में इंसानों से गंदे नालों और सेप्टिक टैंकों को साफ करवाने की प्रथा अभी भी जारी है और इसमें सैंकड़ों लोगों की जान जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि इस खतरनाक काम को करने के दौरान 2017 में 92, 2018 में 67, 2019 में 116, 2020 में 19, 2021 में 36 और 2022 में 17 सफाई कर्मियों की जान जा चुकी है।

देश के 18 राज्यों के आंकड़े मंत्रालय के पास हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इन पांच सालों में इस तरह की सफाई के दौरान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 51 लोग मारे गए। उसके बाद तमिलनाडु में 48 लोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 44 लोग, हरियाणा में 38 लोग, महाराष्ट्र में 34 लोग और गुजरात में 28 लोग मारे गए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सीवर में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना अधिक है।

इस प्रथा को बंद करने की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज भी गंदे नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई इंसानों से करवाई

हाथों से सीवर की सफाई करने के कार्य को देश में प्रतिबंधित किये जाने के उपरान्त भी किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीवर की सफाई करने वालों की सुध लेते हुये केन्द्र व राज्य सरकारों की जमकर खिंचाई तो की है। मगर कोर्ट के निर्देशों का सरकारों पर कितना असर होता है। इसका पता तो आने वाले समय में ही चल पायेगा। बहरहाल आज भी सीवर में सफाई कर्मियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है।

जाती है। सीवर सफाई के दौरान हादसों में मजदूरों की दर्दनाक मौतों की खबरें आती रहती हैं। अधिकांश जगह आज भी मजदूर सीवर की बिना मास्क, ग्लब्स और सुरक्षा उपकरणों के सफाई करते हैं। सीवर की सफाई करने वालों की मौत होने के साथ ही उन पर निर्भर परिवार भी बेसहारा हो जाता है। परिवार की आमदनी का जरिया अचानक से बंद हो जाता है। देश में जाम सीवर की मरम्मत करने के दौरान प्रतिवर्ष दम घुटने से काफी लोग मारे जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी गंदगी साफ करने वाले हमारे ही जैसे इंसानों की जान कितनी सस्ती है। सीवर सफाई के काम में लगे लोगों को सामाजिक उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता है।

देश में पिछले एक वर्ष में सीवर की सफाई करने के दौरान 200 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इस अमानवीय त्रासदी में मरने वाले अधिकांश लोग असंगठित दैनिक मजदूर होते हैं। इस कारण इनके मरने पर कहीं विरोध दर्ज नहीं होता है। देश में करीबन 27 लाख सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसमें से 20 लाख ठेके पर काम करते हैं। एक सफाईकर्मी की औसतन कमाई 7 से 10 हजार रुपये प्रति माह तक होती है। गंदगी में काम करने से आधे से अधिक सफाई कर्मी तो कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इस कारण अधिकांश गटर साफ करने वाले लोगों की कम उम्र में ही मौत हो जाती है। गटर साफ करने वाले लोगों के लिये बीमा की भी कोई सुविधा नहीं होती है।

आमतौर पर सीवर में उतरने से पहले सफाईकर्मी शराब पीते है। शराब पीने के बाद शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तभी सीवर में उतरते ही इनका दम घुटने लगता है। सफाई का काम करने के बाद उन्हें नहाने के लिए साबुन, नहाने तथा पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी कार्यकारी एजेंसी की होती है। इसके बावजूद ये उपकरण और सुविधाएं इनको अभी तक नहीं मिल पा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व भी कई बार सीवर में होने वाली मौतों पर चिंता जताने के साथ ही सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मनुष्य के साथ मनुष्य द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना सबसे अधिक अमानवीय आचरण है। इन परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में लोगों को इस तरह के गैस चैम्बरों में मरने के लिये नहीं भेजा जाता है। कोर्ट ने कहा था कि संविधान में प्रावधान है कि सभी मनुष्य समान हैं। लेकिन उन्हें समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।

कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीवर की सफाई करने वाली एजेंसी के पास सीवर लाईन के नक्शे, उसकी गहराई से सम्बंधित आंकड़े होना चाहिए। सीवर सफाई के काम में लगे लोगों की नियमित स्वास्थ्य की जांच, नियमित प्रशिक्षण देने के नियम का पालन होता कहीं नहीं दिखता है। सभी सरकारी दिशा-निर्देशों में दर्ज है कि सीवर सफाई करने वालों को गैस-टेस्टर, गंदी हवा को बाहर फेंकने के लिए ब्लोअर, टॉर्च, दस्ताने, चश्मा और कान को ढंकन का कैप, हैलमेट मुहैया करवाना आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस बारे में कड़े आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद ये उपकरण और सुविधाएं गायब हैं। सीवर लाइनों की लंबाई तो हर दिन बढ़ रही है। वहीं सफाई करने वालों की संख्या में कमी की जा रही है।

मैनुअल स्केवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम के तहत भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को 2013 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन इस कानून में कुछ शर्तों के साथ गंदे नालों और सेप्टिक टैंकों की इंसानों द्वारा सफाई कराने की इजाजत है। इन शर्तों के तहत सफाई के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य है। लेकिन अक्सर नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

राजस्थान में सीकर जिले के फतेहपुर में सीवरेज की खुदाई के दौरान हुई तीन मजदूरों की मौत के मामले में अपर जिला न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये कंपनी के इंजीनियर सहित तीन लोगों को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुये दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने माना कि काम कर रहे मजदूरों के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना कम्पनी की जिम्मेदारी थी। उस दिन कम्पनी की ओर से सीवरेज का काम किया जा रहा था। वहां सुरक्षा संबंधी पर्याय उपाय नहीं करने के कारण तीन मजदूरों को जान गंवानी पड़ी थी।

भारत में 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले : नीति आयोग

भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। नीति अयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सोमवार को आयोग की 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023' रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, '' भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो 2015-16 में 24.85 प्रतिशत थी और 2019-21 में कम होकर 14.96 प्रतिशत रह गई थी।'' राष्ट्रीय एमपीआई (बहुआयामी गरीबी सूचकांक) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में आभावों को मापता है। इन्हें 12 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़े संकेतकों से दर्शाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट में 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान किए गए हैं रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। एमपीआई मूल्य पांच वर्ष में 0.117 से घटकर 0.066 हो गया और 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की गहनता 47 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत पर आ गई। इससे प्रतीत होता है कि भारत 2023 की निर्धारित समयसीमा की तुलना से काफी पहले एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा घटाने के लक्ष्य) को हासिल कर लेगा। नीति आयोग ने कहा कि सरकार के स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर ध्यान देने से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सुधारों के बल पर भारत ने लगाई लंबी छलांग'

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे 'ऐतिहासिक' सुधारों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जबर्दस्त खर्च से भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने सोमवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक 31 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह बात कही गई है।

बर्नस्टीन की 'पीएम मोदी के नेतृत्व का दशक- एक लंबी छलांग' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि विरासत में संकट में फंसे कई संस्थानों के साथ एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिलने के बावजूद ऐतिहासिक सुधारों, महंगाई पर नियंत्रण, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण के मोर्चे पर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। रिपोर्ट कहती है, 'भाग्य रातोंरात चमकता है - कुछ के लिए, यह किस्मत से होता है, और ज्यादातर के लिए वर्षों के प्रयास से। भारत कुछ इसी तरह की कहानी है।'

इसमें कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में जबर्दस्त प्रगति देखी है। इसमें डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था को संगठित करना, बेहतर नीतिगत माहौल से विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना शामिल है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले दशक के कई साल के दौरान आर्थिक वृद्धि सुस्त रही है, लेकिन सरकार ने नए सुधारों के जरिये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है।

बर्नस्टीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने नौ साल पहले 'अच्छे दिन के वादे' के साथ शानदार जीत हासिल की और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने, लालफीताशाही को कम करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और कारोबारी धारणा में सुधार का वादा किया था। भाजपा के 2014 के चुनाव घोषणापत्र में सुशासन के साथ- साथ आर्थिक समृद्धि का वादा सबसे ऊपर था। भाजपा ने ऊंची वृद्धि, अधिक रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ाने का वादा किया था।

बर्नस्टीन ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ मानदंडों का आकलन किया है। इसमें देखा गया है कि इन मानदंडों पर 2014 के बाद से कैसा प्रदर्शन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि सालाना आधार पर 5.7 प्रतिशत रही है। कोविड-पूर्व की वृद्धि 6.7 प्रतिशत रही थी। वहीं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के कार्यकाल में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत से कुछ कम रही थी। उस दौर में निचले आधार प्रभाव का लाभ मिला था।

इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार को 'विरासत में एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिली थी और कई संस्थान संकट में थे। रिपोर्ट में इसके लिए संप्रग सरकार के कदमों को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर जीडीपी के मामले में पांचवें स्थान पर आ गया है। 2014 में भारत दसवें स्थान पर था। हालांकि, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सूची में भारत काफी पीछे 127वें स्थान पर है। यहां भी 2014 की तुलना में भारत की स्थिति सुधरी है। 2014 में भारत 147वें स्थान पर था।

पांच सालों में एक हजार से अधिक फर्जी मार्कशीट बनाई, हर डिग्री का अलग दाम

विजय नगर थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के दो आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरोह पिछले पांच सालों से फर्जी मार्कशीट बनाने का काम कर रहा है। अब तक एक हजार से अधिक फर्जी मार्कशीट बना चुके हैं। आरोपित 10वीं, 12वीं, बीएचएमएस, बीएएमएस, बी-फार्मा, एम-फार्मा, डी-फार्मा, लैब-टेक्नीशियन आदि की फर्जी मार्कशीट बनाते थे।

आरोपित बिहार, पंजाब, दिल्ली, मप्र, राजस्थान आदि राज्यों की कई यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी मार्कशीट बना चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया है। मामले में आरोपित दिनेश पुत्र सेवकराम तिरोले (41) निवासी गणेशधाम कालोनी (खंडवा नाका) और मनीष राठौर निवासी उज्जैन को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल, पुलिस थाने में आशीष श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आशीष ने बताया था कि आरोपित ने कहा कि कालेज में एडमिशन करवा देगा और तीन साल की डिग्री भी बगैर कालेज आए पूर्ण करवा देगा। आरोपित ने 45 हजार रुपये में सौदा किया और 10 हजार रुपये एडवांस ले लिए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

वेबसाइट पर अपलोड करते थे

आरोपित वेबसाइट पर भी मार्कशीट अपलोड करते थे, ताकि लोगों को लगे कि यह फर्जी मार्कशीट नहीं है। आरोपित दिनेश पहले शिक्षक था। इसके बाद परीक्षा सेंटर बनाने का काम शुरू किया। हमें यह भी पता चला है कि मार्कशीट में जो परीक्षा सेंटर लिखे गए हैं, वे भी फर्जी हैं। वहीं आरोपित मनीष उज्जैन में फर्जी मार्कशीट बनवाता था।

फार्मा की मार्कशीट के लेते थे लाखों रुपये

डीसीपी अभिषेक आनंद ने बताया कि हम लंबे समय से गिरोह को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। आरोपित 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट के 20 हजार और फार्मा की मार्कशीट के लिए लाखों रुपये लेते थे। इनके पास से कई यूनिवर्सिटी की मार्कशीट और सील भी मिली है। यह काफी बड़ा गिरोह हो सकता है, जिसका हम पता लगा रहे हैं। हमें एक मार्कशीट भोपाल की ग्लोबल टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी की मिली थी, जिस पर हमने कालेज प्रबंधन से पूछताछ की तो उनका जवाब आया कि यह फर्जी मार्कशीट है, हमारे कालेज की नहीं है। हम अभी यह पता लगा रहे हैं कि गिरोह में कौन-कौन जुड़ा है और जिन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मिली है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी।

विभिन्न राज्यों के 'लव जिहाद' कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है : फडणवीस

फडणवीस ने राज्य से कथित तौर पर अन्यत्र ले जाई गई परियोजनाओं पर श्वेत पत्र द्वारा राज्य सरकार को दी गई क्लीनचिट के संबंध में भाजपा को महाराष्ट्रद्रोही (महाराष्ट्र से नफरत करने वाला) कहने के लिए शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे की आलोचना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे लग रहा था कि आदित्य ठाकरे मुद्दे का अध्ययन करने के बाद बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है, उसे जवाब देने का क्या मतलब है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लाने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले अन्य राज्यों के इसी तरह के कानूनों का अध्ययन करेगी। फडणवीस ने कहा, लड़कियों की शादी और धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आए हैं। हर तरफ से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है। इससे पहले मैंने सदन में भी घोषणा की थी। इसके मुताबिक विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन जारी है और महाराष्ट्र में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मोदी उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर शीर्ष अदालत द्वारा शुक्रवार को रोक लगाने के बारे में फडणवीस ने विपक्षी दल पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देता है तो यह (निर्णय) अच्छा है अन्यथा यह बुरा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि ऐसे लोग भारत के संविधान के तहत बनाई गई संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गांधी द्वारा दिया गया बयान उचित नहीं था। कांग्रेस और कुछ पार्टियां उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना कर रही हैं। फडणवीस यहां महाराष्ट्र पुलिस अकादमी (एमपीए) में पासिंग आउट परेड में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। एकनाथ शिंदे नीत सरकार में फडणवीस के पास गृह विभाग है।

नगरवासियों एवं देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

// अपील//

- निकाय द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत सम्पात्तिकर/जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर यथा समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
- जल ही जीवन है, जल का दुरुपयोग न करें।
- भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जल स्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
- नगर पालिका की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें।
- नगर को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें, कचड़ा नियत स्थानों पर ही डालें
- जन्म-मृत्यु का पंजीयन, समय पर करायें, तथा निकाय से कम्प्यूटरीकृत जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद डबरा

सत्येन्द्र दुबे
उपाध्यक्ष,नगर पालिका परिषद डबरा

प्रदीप भदौरिया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद डबरा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, डबरा जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

रामजानकी राजेश पण्डा
अध्यक्ष नगर परिषद पीछोर

इरफान खान, उपाध्यक्ष
नगर परिषद पीछोर

पीयूष श्रीवास्तव, मुख्य
नपा अधिकारी, पीछोर

सभी पिछोर नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपील

1. निकाय द्वारा जारी कंप्यूटरीकृत संपत्ति कर जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
2. जल ही जीवन है जल का दुरुपयोग ना करें।
3. भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
4. नगर पालिका की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करें।
5. नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें कचरा नियत स्थानों पर ही डालें।
6. जन्म मृत्यु का पंजीयन समय पर कराएं तथा निकाय से कंप्यूटरीकृत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
7. नगर पालिका से अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें।
8. शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।
9. नगर में वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का का कांग्रेस पर निशाना, बोले-

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जनता को भगवान मानती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, वहां रहने वाले लोग मेरे भगवान हैं और हम उस भगवान के पुजारी हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं। क्या यही आपकी 'मोहब्बत की दुकान' है?

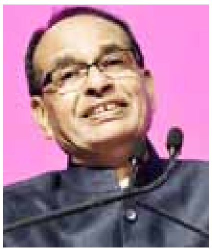

मध्य प्रदेश में राजनीति जबकर हो रही है। कांग्रेस और भाजपा पर वार-पलटवार की राजनीति भी जमकर हो रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने का कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता जनता को राक्षस कह रहे हैं... क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों लोग 'राक्षस' हैं? इसके साथ ही उन्होंने आगे सवाल किया कि आप (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) क्या मानते हैं? क्या आप जनता को 'राक्षस' मानते हैं?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जनता को भगवान मानती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, वहां रहने वाले लोग मेरे भगवान हैं और हम उस भगवान के पुजारी हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं। क्या यही आपकी 'मोहब्बत की दुकान' है? रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। मुझे लगता है ये असंसदीय भाषा है, हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। रणद ीप सुरजेवाला ने कहा था कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से श्राप देता हूं।

इसके बाद, भारतीय जनता के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक्स ट्विटर पर सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी, जो बार-बार राजकुमार को लॉन्च करने में विफल रही, अब जनता और जनार्दन को गाली देना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विरोध में अंधता का शिकार हो चुके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सुनिए, जो कह रहे हैं- ''देश की जो जनता बीजेपी को वोट और सपोर्ट करती है, वो 'राक्षस' हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। मुझे लगता है ये असंसदीय भाषा है, हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे।

बिलौआ नगर परिषद की ओर से सभी नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एव अपील

1.स्वच्छता बनाये रखे, 2.जल, मकान, टेक्स समय पर जमा कराए 3. कचरा कचरा गाड़ी मैं ही डाले...

श्रीमती विजयलक्ष्मी चौरसिया
अध्यक्ष : नप बिलौआ

अनीता राम अवतार रावत
उपाध्यक्ष, बिलौआ

सुनील चौरसिया
पार्षद बिलौआ

पीयूष श्रीवास्तव
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

अपीलकर्ता : नगरपालिका

भारत की एक और दवा को लेकर अलर्ट, WHO ने बताया दूषित और घातक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इराक में बेचे जाने वाले भारत निर्मित सामान्य कोल्ड सिरप के एक बैच पर अलर्ट जारी किया। डब्ल्यूएचओ ने उत्पाद को दूषित और यूज के लिए असुरक्षित पाया गया। कोल्ड आउट ब्रांड नाम का यह सिरप इराक में बेचा जा रहा था और डाबीलाइफ फार्मा के लिए फोर्ट्स (इंडिया) लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित किया जा रहा था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने पाया कि सिरप में प्रदूषकों डायथिलीन और एथिलीन ग्लाइकॉल - की स्वीकार्य सीमा से अधिक थी। अपने मेडिकल उत्पाद अलर्ट में, डब्ल्यूएचओ ने कहा कि सिरप के बैच में 0.25 प्रतिशत डायथिलीन ग्लाइकॉल और 2.1 प्रतिशत एथिलीन ग्लाइकॉल था, जबकि इन दोनों के लिए स्वीकार्य सुरक्षा सीमा 0.10 प्रतिशत तक है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, निर्माता और विपणनकर्ता ने उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में एजेंसी को गारंटी नहीं दी। कंपनियों ने अभी तक आरोपों और डब्ल्यूएचओ की चेतावनी का जवाब नहीं दिया है। अब तक, भारतीय निर्माताओं से जुड़े पांच 'दूषित' सिरप जांच के दायरे में आ चुके हैं। पिछले महीने, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने मध्य प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ समन्वय में फार्मा फर्म रीमैन लैब्स को अपने कफ सिरप का निर्माण रोकने का निर्देश दिया था, जो कैमरून में बच्चों की मौत से जुड़ा था।

यह तब हुआ जब डब्ल्यूएचओ ने कैमरून में आपूर्ति किए गए कफ सिरप के संबंध में एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि एक विश्लेषण में पाया गया कि उत्पाद में संदूषक के रूप में डायथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा थी। इससे पहले, भारत निर्मित कफ सिरप को कथित तौर पर पिछले साल गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में क्रमशः 66 और 18 बच्चों की मौत से जोड़ा गया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा कफ सिरप से होने वाली मौतों को भारत में बनी दवाओं से जोड़ने के बावजूद, देश का फार्मास्युटिकल निर्यात इस वित्तीय वर्ष में 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है।

फ्लाइंग किस विवाद पर महुआ मोइत्रा का स्मृति इरानी पर वार

महुआ ने पूछा - आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं ?

महुआ मोइत्रा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद को लेकर उन्होंने (ईरानी) एक शब्द भी नहीं कहा और अब वह 'फ्लाइंग किस' की बात कर रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह प्रस्ताव सदन में सफल होने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पर अविश्वास से अधिक, यह प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में 'विश्वास रखें' के बारे में है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मणिपुर की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अलग है और मणिपुर में 'घृणा अपराध, गृह युद्ध' है। जब मणिपुर की स्थिति की तुलना अन्य राज्यों से किए जाने पर महुआ मोइत्रा ने इसे 'झूठा प्रसार' कहा। इसका जवाब देते हुए सांसद ने कहा मुद्दा यह है कि मणिपुर में दो समुदाय गृहयुद्ध के माहौल में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पिछले 3 महीनों में 6,500 एफआईआर? यह किस राज्य ने देखा है।"

मोदी पर वार

महुआ मोइत्रा ने कहा कि "पीएम मोदी, अगर आप सुन रहे हैं...मैं मणिपुर के लोगों की ओर से आपसे विनती करती हूं। प्रशासन बदलें, सभी पक्षों को युद्धविराम के लिए काम करने दें। अन्यथा, आपका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, भारत एक स्वर में कहेगा कि मणिपुर में क्या गलत हुआ।" उन्होंने कहा कि भारत ने आप पर से भरोसा खो दिया है। महानतम लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का नई संसद के कक्ष में बहुसंख्यक धार्मिक संतों के सामने झुकने का दृश्य हमें शर्म से भर देता है, चैंपियन पहलवानों के खिलाफ पुलिस की मारपीट और एफआईआर दर्ज करना हमें शर्म से भर देता है, भाजपा के 3 जिलों में 50 पंचायतें- शासित हरियाणा द्वारा मुस्लिम व्यापारियों को राज्य में प्रवेश करने से मना करने संबंधी पत्र जारी करना हमें शर्म से भर देता है।

स्मृति ईरानी पर तंज

महुआ मोइत्रा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद को लेकर उन्होंने (ईरानी) एक शब्द भी नहीं कहा और अब वह 'फ्लाइंग किस' की बात कर रही हैं। मोइत्रा का यह बयान लोकसभा में राहुल गांधी से जुड़े फ्लाइंग किस विवाद पर स्मृति ईरानी के बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सांसद को स्त्रियों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा था कि सदन में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। इस घटना को लेकर भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की थी और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने कहा, '' आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं मैडम।''

वैज्ञानिकों ने 'अज्ञात महामारी' को लेकर जताई आशंका, 2018 में ही डब्ल्यूएचओ ने कर दिया था अलर्ट

पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर 'डिजीज एक्स' ट्रेंड कर रहा है। यह अज्ञात बीमारी इन दिनों काफी चर्चा में है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभवतः यह नई महामारी का संकेत भी हो सकती है। फिलहाल अब तक यह ज्ञात नहीं है कि कौन से वायरस या रोगजनक के कारण यह बीमारी हो सकती है, क्या यह भी जानवरों से मनुष्यों में खतरा बनेगी और शायद एक और महामारी का कारण रूप भी ले सकती है?

इस अज्ञात और अप्रत्याशित महामारी के लगातार बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में 200 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए वैक्सीन पर काम भी शुरू कर दिया है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी और वैक्सीन निर्माताओं का कहना है कि हम 100 दिनों के भीतर इसके लिए सुरक्षात्मक टीके तैयार कर लेंगे, ताकि हमें एक बार फिर से कोविड-19 जैसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। जिस अज्ञात 'डिजीज एक्स' को लेकर वैज्ञानिकों की टीम में चर्चा है, असल में वह कोई नया शब्द नहीं है। साल 2018 की भी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि डिजीज एक्स- हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संक्रामक खतरा बन सकती है। इतना ही नहीं कोविड-19 महामारी शुरू होने से लगभग दो साल पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने डिजीज एक्स को अपनी प्राथमिकता वाली बीमारियों की ब्लूप्रिंट सूची में जोड़ा था। यह उन बीमारियों की सूची थी जिनके लिए स्वास्थ्य संगठन ने त्वरित अनुसंधान और विकास की तत्काल आवश्यकता निर्धारित की थी।

डिजीज एक्स- क्या है वैज्ञानिकों की राय : स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम कहती है, अस्पष्ट और अपरिभाषित प्रकृति के कारण इस बीमारी का उपनाम 'डिजीज एक्स' रखा गया है। यह भविष्यवाणी करना कि कौन सा संभावित रोगजनक अगली महामारी को ट्रिगर करेगा, यह एक पहेली बनी हुई है। शोधकर्ताओं का इसको लेकर अलग-अलग मत है। एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या, नई महामारी की आशंका को बढ़ा रहे हैं। शहरीकरण और बदलते पारिस्थितिकी तंत्र ने क्रॉस-प्रजाति वायरल ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे दिया है, बर्ड फ्लू इसका उदाहरण हैं।

महामारी से बचाव को लेकर भी तैयारी

वैज्ञानिकों का कहना है, हम उन वायरस और बैक्टीरिया पर गौर कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले से पता है कि वे खतरा पैदा कर सकते हैं। इन रोगजनकों के कारण होने वाली संभावित बीमारी को लेकर मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया जा रहा है, जिससे इसके संभावित जोखिमों को कम करने में मदद मिल सके। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस (MERS-COV) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS), ये दोनों कोरोना वायरस पिछले दो दशकों के दौरान पहले ही प्रकोप का कारण बन चुके हैं। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य की चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि हम संभावित महामारी के पहले से इससे बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर लेंगे।

बोले अमित शाह-
एक वोट से गिरी थी अटलजी की सरकार; कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचार का, हम वैसे नहीं

संसद में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को फिर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और मणिपुर का मुद्दा उठाया। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे राजनीतिक दलों और पार्टियों के चरित्र उजागर होते हैं।

आगे अमित शाह ने कहा कि मैं तीन प्रस्तावों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। दो प्रस्ताव हम लेकर आए थे, एक एनडीए सरकार के खिलाफ आया। जुलाई 1993 में नरसिंह राव जी की सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव आया। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। नरसिंह राव जी की सरकार जीत गई, लेकिन बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर यह जीत हासिल की गई।

साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में मनमोहन सिंह विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस देने पड़ी। हमारे सांसद रुपया लेकर सामने आई। उन्होंने सरकार बचा ली। इसके सामने दूसरा उदाहरण है 1999 का। अटलजी की सरकार के समय अविश्वास प्रस्ताव आया। जो कांग्रेस ने किया, वह हम कर सकते थे। नरसिंह राव जी साबित कर चुके थे कि करोड़ों रुपये देकर सरकार बचाई जा सकती है।

अमित शाह ने बोला कि अटलजी ने इसी जगह बैठकर कहा कि संसद के फैसले को सिर पर चढ़ाऊंगा। सिर्फ एक वोट से सरकार गई। हम यूपीए और कांग्रेस की तरह सरकार बचा सकते थे। कांग्रेस का चरित्र भ्रष्टाचार का है, हमारा चरित्र वैसा नहीं है। एक ही वोट का फर्क था। एनडीए सरकार ने स्पीकर के पद की गरिमा का भी पालन किया था। हमारी सरकार चली गई। जनता है जो सब देखती है, सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, लेकिन अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटलजी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। अटलजी के नेतृत्व में तब और मोदी जी के नेतृत्व में हम सिद्धांतों की राजनीति बचाने के लिए यहां हैं।

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशनभोगी करेंगे भूख हड़ताल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना ईपीएस-95 के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किये जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत फिलहाल पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन निर्धारित की गयी है।

यह व्यवस्था सितंबर, 2014 में लागू की गयी थी। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने बुधवार को बयान में कहा, ''हम अपनी मांगों के समर्थन में बृहस्पतिवार 20 जुलाई को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे।'' बयान के अनुसार, ''ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें ईपीएस-95 पेंशनभोगी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी सेवा समर्पित की थी लेकिन उन्हें बेहद कम पेंशन राशि के कारण गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत (सेवानिवृत्त) ने कहा, ''ये पेंशनभोगी बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी गरिमा खो रहे हैं।'' बयान के अनुसार, ''इसीलिए 20 जुलाई को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के पेंशनभोगी उसी दिन प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल भी करेंगे।

पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगी के जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।

भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर : मार्टिन वुल्फ

भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से दुनिया में'तेजी से एक बड़ी ताकत' बनने की ओर अग्रसर है और 2050 तक इसका आकार अमेरिका के बराबर होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने यह बात कही है। वुल्फ ने इसके साथ ही कहा कि पश्चिमी देशों के नेता सोच- विचार कर भारत पर दांव लगा रहे हैं। वुल्क ने 'द फाइनेंशियल टाइम्स' में लिखे लेख में कहा, 'मैं मानता हूं कि भारत 2050 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को पांच प्रतिशत या इसके आसपास बनाए रख सकता है। बेहतर नीतियों से वृद्धि इससे ऊंची भी रह सकती है।

हालांकि, यह इससे कुछ कम भी रह सकती है।' उन्होंने कहा कि भारत 'चीन प्लस वन' रणनीति को अपनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। बड़े घरेलू बाजार की वजह से इस मामले में अन्य प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भारत लाभ की स्थिति में है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1.67 अरब पर पहुंच जाएगी। अभी भारत की आबादी 1.43 अरब है।

वुल्फ ने कहा कि देश के बैंकों का बही- खाता बेहतर हो गया है। ऋण वृद्धि भी अब बेहतर आकार ले रही है। उन्होंने लिखा कि आगामी दशकों में देश की अर्थव्यवस्था और आबादी दोनों तेजी से बढ़ेगी। इससे भारत, चीन को टक्कर देगा। भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जो एक अच्छी बात है। वुल्फ ने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कभी प्रतिबंधित रहे नरेन्द्र मोदी का वॉशिंगटन में गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस में इमैनुएल मैक्रों ने भी भारतीय नेता को उतनी ही गर्मजोशी से गले लगाया। यह एक ऐसे देश के साथ नजदीकी संबंधों को दर्शाता है, जो चीन के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी साबित हो सकता है।'

उन्होंने कहा, 'क्या यह पश्चिमी ताकतों का अच्छा दांव है? हां, निश्चित रूप से भारत तेजी से बढ़ती ताकत है। उनके हितों में भी सामंजस्य है।' उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2023 से 2028 तक वार्षिक आर्थिक वृद्धि छह प्रतिशत से कुछ अधिक रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद इससे लगभग एक प्रतिशत अंक कम की रफ्तार से बढ़ेगा। वुल्फ ने कहा कि यदि वैश्विक या घरेलू स्तर पर कोई बड़े झटके नहीं लगते हैं, तो यह वृद्धि पिछले तीन दशक के औसत के बराबर होगी।

उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है, जिसके श्रमबल की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, बचत की दर काफी ऊंची है और अधिक समृद्धि की व्यापक उम्मीदें हैं। वुल्फ ने कहा कि 2050 तक भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति के आधार पर) उसी स्तर पर होगा, जहां आज चीन है। वुल्फ ने यह अनुमान भारत की वार्षिक वृद्धि पांच प्रतिशत तथा अमेरिका की 1.4 प्रतिशत रहने के आधार पर लगाया है।

उन्होंने कहा कि भारत की आबादी भी अमेरिकी की तुलना में 4.4 गुना होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2050 तक अमेरिका के समान होगा। ऐसे में पश्चिमी नेता समझदारी से भारत पर दांव लगा रहे हैं। इससे पहले भारत की यात्रा पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने बुधवार को कहा था कि घरेलू खपत की वजह से वैश्विक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है।

भारत में पेड़ों की 347 प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा...

राज्य में औसतन 32 प्रजातियां संकटग्रस्त

इससे जुड़ा अध्ययन जर्नल बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में प्रकाशित हुआ है। भारत जैव-विविधता से समृद्ध देश है। यही वजह है कि दुनिया के 36 प्रमुख जैवविविधता हॉटस्पॉट्स में भारत के चार क्षेत्र भी शामिल है। भारत में पेड़ों की 3,708 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 347 यानी 9.4 फीसदी प्रजातियां खतरे में हैं। वहीं, 609 प्रजातियां ऐसी भी है जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। यह जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा पेड़ों की विविधता और स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए तैयार डाटाबेस 'ट्रीज ऑफ इंडिया' (टीओआई) में सामने आई है।

इससे जुड़ा अध्ययन जर्नल बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में प्रकाशित हुआ है। भारत जैव-विविधता से समृद्ध देश है। यही वजह है कि दुनिया के 36 प्रमुख जैवविविधता हॉटस्पॉट्स में भारत के चार क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि इसके बावजूद देश में पेड़ों की विविधता के बारे में आंकड़ों का अभाव है। शोधकर्ता अंजार अहमद खुरू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 1872 से 2022 के बीच प्रकाशित 313 अध्ययनों का विश्लेषण किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अध्ययन उन क्षेत्रों में संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं और पारिस्थितिक की बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों में मददगार होगा। रिपोर्ट में पेड़ों पर मंडराते खतरे की सबसे बड़ी वजह जंगलों की बेतहाशा कटाई, शहरीकरण माना गया है।

तमिलनाडु सबसे ज्यादा विविधता

अध्ययन में सामने आया कि भारत के हर राज्य में औसतन पेड़ों की 606 प्रजातियां है। हर प्रजाति कम से कम छह राज्यों में पाई जाती है। देश में पेड़ों की सबसे ज्यादा विविधता तमिलनाडु में है। इसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता हैं। पेड़ों की सबसे कम संख्या लद्दाख में रिकॉर्ड की गई है।

राज्यों में औसतन 36 स्थानीय प्रजातियों पर भी संकट

शोध से यह भी पता चला है कि देश के हर राज्य में औसतन पेड़ों की करीब 32 संकटग्रस्त और 36 स्थानीय प्रजातियां हैं। वहीं, प्रत्येक स्थानीय प्रजाति करीब दो राज्यों में पाई जाती है। केरल में संकटग्रस्त और स्थानीय दोनों प्रकार की ही प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की बारी आती है। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में पेड़ों की दो-दो स्थानीय प्रजातियां हैं, जबकि लद्दाख, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में यह पूरी तरह नदारद हैं। बॉटनिक गार्डंस कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज के अनुसार देश में पेड़ों की कुल 2,611 प्रजातियां हैं।

लुप्त होने की कगार पर पहुंचीं कई समुद्री प्रजातियां...

बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में आग का प्रकोप भी बढ़ा है। अल्जीरिया, ग्रीस, इटली और स्पेन सहित भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और हजारों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है।

अमेरिका से लेकर चीन तक पूरा उत्तरी गोलार्ध इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। इसकी वजह से न केवल लोगों के स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार उत्तरी गोलार्ध का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में तापमान औसत से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया।

इसकी वजह से समुद्र में लू की स्थिति बन गई है। यह कई समुद्री प्रजातियों की विलुप्ति तक का कारण बन सकती है। वहीं, भीषण बारिश और बाढ़ ने भी क्षेत्र में व्यापक असर डाला है। इसका असर पूरी दुनिया में भी देखने को मिला है। अनेक लोग हताहत हुए हैं और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में आग का प्रकोप भी बढ़ा है। अल्जीरिया, ग्रीस, इटली और स्पेन सहित भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और हजारों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। वहीं, तीन ग्रीक द्वीपों रोड्स, इविया और कोर्फू से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया है।

डब्ल्यूएमओ के अनुसार 16 जुलाई को चीन के शिनजियांग प्रांत में तापमान 52.2 डिग्री तक पहुंच गया था। यह देश में उच्चतम तापमान का एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह अमेरिका के फीनिक्स में भी लगातार 31 दिनों तक तापमान 43.3 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया।

बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं के प्रवेश पर रोक

एडमिनिस्ट्रेशन की दो टूक- ड्रेस कोड पर आपत्ति तो कॉलेज छोड़ने के लिए स्वतंत्र

कॉलेज ने एक बयान जारी कर कॉलेज के लिए तैयार होने के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ सशर्त नियमों को स्पष्ट किया। कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने घटना के बारे में बोलते हुए कहा कि कॉलेज ने इस साल एक ड्रेस कोड लागू किया है और नियमों के बारे में अभिभावकों को पहले ही बता दिया गया था। मुंबई के चेंबूर में एक कॉलेज ने बुधवार को कॉलेज की यूनिफॉर्म नीति के कारण बुर्का पहनने वाली छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस घटना से तनाव फैल गया क्योंकि छात्राओं के माता-पिता ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन किया, जबकि विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और अभिभावकों के साथ-साथ कॉलेज अधिकारियों के समझाने के बाद स्थिति शांत हुई। शाम तक, कॉलेज ने एक बयान जारी कर कॉलेज के लिए तैयार होने के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ सशर्त नियमों को स्पष्ट किया। कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने घटना के बारे में बोलते हुए कहा कि कॉलेज ने इस साल एक ड्रेस कोड लागू किया है और नियमों के बारे में अभिभावकों को पहले ही बता दिया गया था।

1 मई को हमने इस नई ड्रेस कोड नीति पर चर्चा करने के लिए माता-पिता के साथ एक बैठक की। हमने बुर्का, हिजाब, स्कार्फ और स्टिकर पर प्रतिबंध सहित हर चीज के बारे में सूचित किया था। उस वक्त ड्रेस कोड पर सभी ने सहमति जताई थी। लेकिन वे अब विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी छात्रा ड्रेस कोड पर आपत्ति जताती है, वह कॉलेज छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच, कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि उन्हें हिजाब या बुर्का पहने बिना घर से निकलने में असहजता महसूस होती है क्योंकि यह उनके लिए एक धार्मिक प्रथा है। उन्होंने अपने आराम के लिए कम से कम स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी।

उदयपुरा नगर परिषद की ओर से स्वतंत्रता दिवस की उदयपुरा नगरवासियों को

हार्दिक शुभकामनाएं

अध्यक्ष
श्रीमती सीमा व्रजेंद्र सिंह राजपूत

उपाध्यक्ष
श्रीमती बैशाली पिता बृजगोपाल लोया

सीएमओ महेश पुरोहित
एवं समस्त नगर परिषद एवं पार्षद गण

अपील

1. संपति कर जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर ऐसा समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
2. जल ही जीवन है जल का दुरुपयोग ना करें।
3. पवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
4. नगर परिषद की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करें।
5. नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें कचरा नियत स्थानों पर ही डालें।
6. जन्म मृत्यु का पंजीयन समय पर कराएं तथा निकाय से कंप्यूटरीकृत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
7. नगर परिषद से अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें।
8. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
9. नगर में वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ना उत्तर प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होगा : योगी आदित्यनाथ

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां लोक भवन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं का प्रदेश है, ऐसे में विश्व बैंक के साथ जुड़ना, राज्य के लिए लाभकारी और फलदायी साबित होगा। बुधवार को यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज यहां लोक भवन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश आगमन पर विश्व बैंक के प्रतिनिधिमण्डल का अभिनन्दन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं का प्रदेश है।

ऐसे में विश्व बैंक के साथ जुड़ना, राज्य के लिए लाभकारी और फलदायी साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज नियोजित प्रयासों से बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है तथा नीति आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार विगत छह वर्षों में उत्तर प्रदेश अपनी साढ़े पांच करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत छह वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपना निर्यात दोगुना करने में सफलता पाई है।

बयान में कहा गया कि इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर ने विगत छह वर्षों में प्रदेश के समग्र विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि समूह में शामिल कई प्रतिनिधि एक दशक पहले उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। विश्व बैंक का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश आया है। इस प्रतिनिधिमंडल में दुनिया के 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सम्मिलित हैं।

रेवेन्यू से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। यहां जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरे किए जाए और चकबंदी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके। बयान के अनुसार, योगी ने रबी की फसलों का शत-प्रतिशत 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66619.24 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने पिछले 10 साल से अधिक समय से सार्वजनिक भूमि पर अधिवास कर रहे गरीब, वंचित व दलित असहाय व्यक्तियों को भूमि का पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये भरने के निर्देश दिए।

अंडमान-निकोबार के मुख्य सचिव निलंबित, उपराज्यपाल पर पांच लाख का जुर्माना

अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ के अधिवक्ता गोपाल बिन्नू कुमार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। मुख्यसचिव और उपराज्यपाल प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित कर दिया। जबकि उपराज्यपाल डीके जोशी पर अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना (जो उन्हें अपने कोष से वहन करना होगा) लगाया गया है। श्रमिकों के लाभ को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ ने यह आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष 19 दिसंबर को पारित पहले आदेश में द्वीप प्रशासन द्वारा नियोजित लगभग 4,000 दैनिक रेटेड मजदूरों (डीआरएम) को उच्च वेतन और डीए प्रदान किया गया था। मुख्य सचिव और उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन को अदालत ने डीआरएम के लिए 1/30वें वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ जारी करने के अपने आदेश का पालन न करने के लिए दोषी पाया, जो 2017 से लंबित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति विभास रंजन दे की पीठ ने यह आदेश दिया है। प्रशासन में अगला वरिष्ठतम अधिकारी कार्यभार संभालेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा। मामले की अगली सुनावई 17 अगस्त को होगी।

मामले की जानकारी देते हुए अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ की ओर से पेश हुए वकील गोपाल बिन्नू कुमार ने कहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 4,000 डीआरएम (जिन्हें लाभ नहीं मिला) हैं और 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीआरएम नियमित कर्मचारियों के बराबर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और 1/30वें वेतन और महंगाई भत्ते के वित्तीय लाभ के हकदार हैं। हालांकि 22 सितंबर, 2017 को यहां के स्थानीय प्रशासन ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि डीआरएम को एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चुनिंदा लाभार्थियों को चुना। प्रशासन द्वारा फिर से जारी किए जाने के बाद हमने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी। ज्ञापन में कहा गया है कि छूटे हुए डीआरएम को उनका वेतन 9 मई, 2023 से मिलेगा, न कि 2017 से, जैसा कि अदालत ने निर्देश दिया है।

क्या कांग्रेस जैसा माहौल भाजपा में नहीं मिल रहा है...

नरेन्द्रसिंह तोमर को मिली जिम्मेदारी से सिंधिया गुट क्यों है असहज...

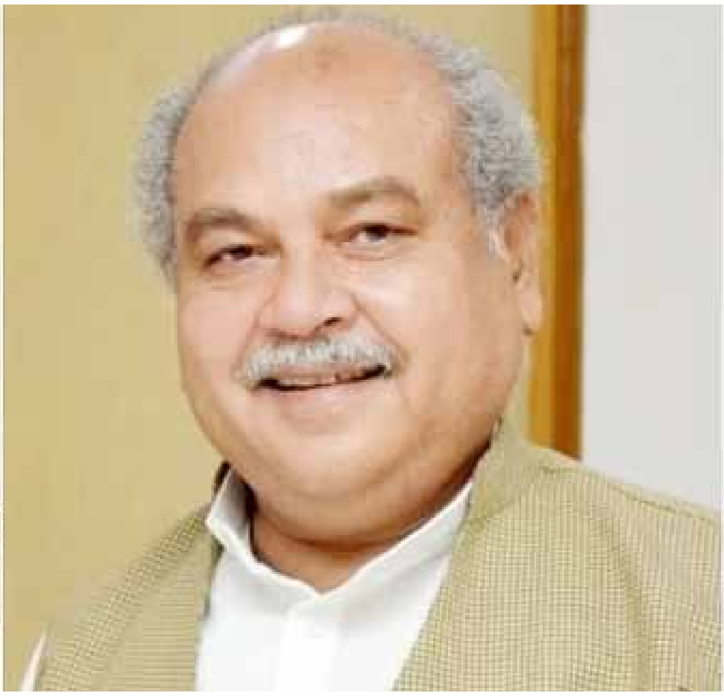

मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। प्रदेश के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अलग से रणनीति बनाई जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की कमान अपने हाथों में ले रखी है। दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच हाईकमान ने क्षत्रपों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देकर हाईकमान ने साफ कर दिया है कि इन चुनावों में वही होगा जो दिल्ली दरबार चाहेगा। मोदी-शाह के करीबी तोमर की इस नियुक्ति ने न केवल सिंधिया बल्कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा जैसे तमाम क्षत्रपों को एक झटका लगा है। क्योंकि ये नेता इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आतुर नजर आ रहे थे। तोमर के जरिए भाजपा हाईकमान सीधे मध्यप्रदेश के घटनाक्रमों पर नजर रख सकेगा।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए झटका भी माना जा रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला तो तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। दूसरा यह भी कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया की तरह तोमर भी ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से आते हैं। पार्टी चुनाव संबंधित समितियों में इस क्षेत्र से और कितने नेताओं को जगह देगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सर्वे में ग्वालियर-चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर बताई जा रही है। इसके अलावा सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि, अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर गोलबंद हो जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि सिंधिया-समर्थक विधायक और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सरकार से लेकर संगठन तक में रखा गया सिंधिया समर्थकों का ध्यान : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी में शामिल हुए करीब तीन साल हो गए हैं, वापस चुनाव आ गए हैं। ग्वालियर-चंबल में भाजपा के पुराने नेता सिंधिया समर्थकों को अपना नहीं पाए हैं। भाजपा ने अपने पुराने नेताओं को तरजीह न देते हुए सिंधिया समर्थकों को न केवल अहम जिम्मेदारी दी है, बल्कि उन्हें कई समितियों और मंडल में जगह भी दी है।

के सवाल पर प्रदेश के राजनीति के जानकारों का कहना है कि सिंधिया को लंबी राजनीति करनी है। वो 2023 के चुनावों में किसी भी पद की शर्त को लेकर या 4-5 उम्मीदवारों के टिकट को लेकर सीधे नेतृत्व की आंखों में खटकने का कोई कदम नहीं उठाएंगे। उनका ध्यान विधानसभा चुनावों के साथ-साथ आगामी लोकसभा चुनावों पर भी है। जहां तक बात उनके समर्थक नेताओं की है तो उन्हें 2020 में पार्टी से जुड़ने के बाद सम्मानित पद दिए गए। जिसे सरकार में जगह नहीं मिली उसे संगठन में जगह दी गई। ऐसा आगे भी जारी रह सकता है। इसी के साथ उन्हें अभी बीजेपी के संगठन को समझना होगा। कांग्रेस जैसा व्यवहार उन्हें बीजेपी में नहीं मिल सकता है।

पार्टी के लिए कमजोर कड़ी बन रहा ग्वालियर-चंबल दुर्ग

सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही दिग्गज नेता ग्वालियर-चंबल इलाके से आते हैं, लेकिन पार्टी की हालत इस क्षेत्र में काफी खराब नजर आ रही है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 34 में से सबसे ज्यादा 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। सिर्फ चंबल की ही बात करें तो यहां की 13 में से 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। सिंधिया के पार्टी से जुड़ने के बाद भी बीजेपी को कुछ खास फायदा इस इलाके में मिलते नहीं दिखा। बल्कि ग्वालियर निगम की सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर पर अहम जिम्मेदारी मिलने के साथ ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो अपने इस इलाके में पार्टी की स्थिति को सुधारें और इस कमजोर दुर्ग को मजबूत करें। आने वाले दिनों में सिंधिया को भी इस इलाके में सक्रिय होने के लिए कहा जा सकता है।

राजस्थान पर पीएम मोदी की पैनी निगाह...

प्रदर्शन-रैलियां और कार्यकर्ताओं की बैठक का खुद ले रहे फीडबैक...

सूत्रों ने बताया कि पार्टी के इस निर्णय के बाद पीएम राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके हैं। आगे की तैयारियों को लेकर अब वे प्रदेश के दोनों सदनों के सांसदों के साथ 8 अगस्त को बैठक करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ विधायक और संगठन से जुड़े लोगों के साथ भी पीएम मोदी बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे...

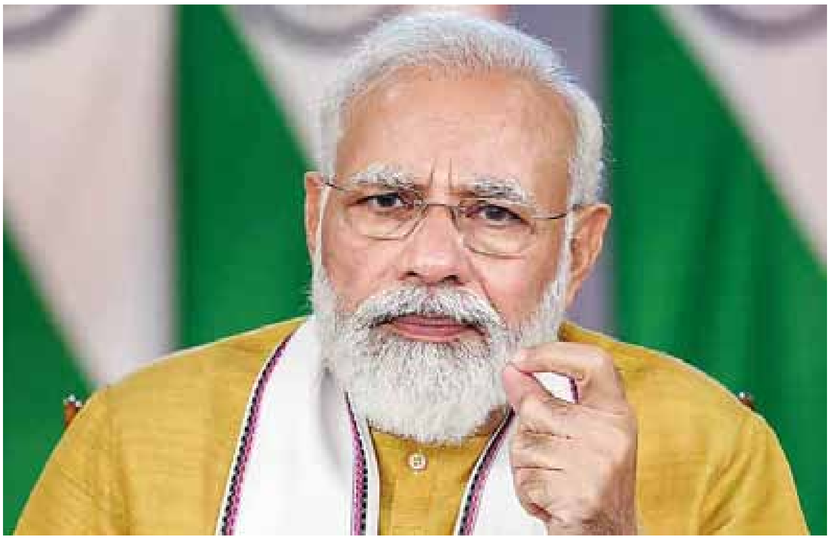

राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ने जा रही है। यही नहीं प्रदेश का चुनावी अभियान अब पीएम मोदी की देखरेख में आगे बढ़ेगा। भाजपा ने अपने चारों शीर्ष नेताओं को चुनावी राज्यों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसमें पीएम राजस्थान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष तेलंगाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी कामकाज देखेंगे।

पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि पार्टी के इस निर्णय के बाद पीएम राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके हैं। आगे की तैयारियों को लेकर अब वे प्रदेश के दोनों सदनों के सांसदों के साथ 8 अगस्त को बैठक करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ विधायक और संगठन से जुड़े लोगों के साथ भी पीएम मोदी बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे। विधायकों की बैठक 25-26 अगस्त के आसपास हो सकती है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर पीएम विधानसभा चुनाव में सक्रिय तौर पर प्रचार तो करते है, लेकिन चुनावी रणनीति पर सीधी निगरानी नहीं रखते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, चुनाव प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के जरिए ही रणनीति बनाई जाती है। लेकिन इस बार पार्टी कार्यकर्ता और संगठन को संदेश देना चाहती है कि पीएम भी संगठन के एक कार्यकर्ता की तरह ही होते हैं।

राजस्थान में वसुंधरा राजे समेत चार बड़े केंद्रीय मंत्री, स्थानीय दिग्गज नेताओं को सीएम पद की दौड़ में माना जाता है। कांग्रेस पार्टी कई बार इसे लेकर भाजपा पर हमला बोलती है। बड़े नेताओं के बीच खींचतान खत्म करने के लिए पीएम मोदी स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं और रणनीति पर चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदी पट्टी के राज्यों में राजस्थान अकेला ही ऐसा राज्य जहां भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी 25 सीटों पर कब्जा किया था। पार्टी 2024 के चुनावों में यह रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है।

सीएम गहलोत-पायलट विवाद और राज्य में सत्ता पलटने के रिवाज को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वह राज्य की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसलिए पीएम मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता की राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब भाजपा पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

आने वाले दिनों में 3 दौरे करेंगे पीएम मोदी

राजस्थान भाजपा के नेताओं के मुताबिक, संसद के मानसूत्र सत्र के खत्म होने के बाद प्रदेश में पीएम के तीन दौरे और हो सकते हैं। पीएम अगस्त में तीन स्थानों पर सभा या दौरे कर सकते हैं। इनमें एक स्थान खरनाल (नागौर) होगा, जहां वे वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद उनकी दो सभा कोटा (हाड़ौती) और भरतपुर (ब्रज-मेवात) या जोधपुर (मारवाड़) संभाग में से किसी एक जगह पर हो सकती है। पीएम मोदी नवंबर 2022 से अब तक राजस्थान में बांसवाड़ा (वागड़), सिरोही (गोडवाड़), अजमेर-पुष्कर (मेरवाड़ा), भीलवाड़ा (मेवाड़), दौसा (ढूंढाड़), बीकानेर (मारवाड़), सीकर (शेखावाटी) में आ चुके हैं। राजस्थान में भाजपा तीन बड़े धार्मिक स्थलों से जनसमर्थन रैलियां निकालने वाली है। इन रैलियों का नेतृत्व कौन करेगा यह भी तय नहीं हुआ है। ये रैलियां रणथंभौर (सवाईमाधोपुर) स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेशजी, लोकदेवता गोगाजी की गोगामेड़ी स्थली (हनुमानगढ़) और आदिवासियों के तीर्थस्थल बेणेश्वर धाम (डूंगरपुर) से निकाली जाएंगी। इन रैलियों के नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और राज्य सभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा आदि के नामों पर विचार किया जा रहा है।

खुद ट्वीट कर सचिवालय घेराव का किया था आह्वान

भाजपा ने एक अगस्त को जयपुर के सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम तय किया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रदेश भाजपा के किसी आंदोलन के लिए स्वयं पीएम मोदी ने ट्वीट किया हो। ट्वीट करके मोदी ने लिखा, 'बेटियों के मान में चलो...गरीबों के उत्थान में चलो...दलित सम्मान में चलो...किसान का दर्द भी सुनो..हुंकार भरो।' हालांकि इससे पहले भी प्रदेश भाजपा ने कई बार आंदोलन किए और विधानसभा का घेराव किया, लेकिन जयपुर प्रदर्शन के लिए पहली बार पीएम मोदी के निजी अकाउंट से ट्वीट कर आह्वान किया गया।

विधायक के बयान से खड़ा हुआ विवाद

सुंदरता देखकर प्रियंका चतुर्वेदी को आदित्य ठाकरे ने सांसद बनाया ?

प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य और शिव सेना (यूबीटी) के उपनेता के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक थीं। सांसद प्रियंका एक बार फिर सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायक संजय शिरसाट ने रविवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) सेना विधायक प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि आदित्य ठाकरे द्वारा उनकी सुंदरता को देखने के बाद चतुर्वेदी ने राज्यसभा में एक पद हासिल किया। उनकी टिप्पणियों की आलोचना हुई और उन्हें स्त्रीद्वेषी करार दिया गया।

हालांकि, बाद में शिरसाट ने इस टिप्पणी के लिए पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे को जिम्मेदार ठहराया, जो उद्धव ठाकरे गुट से हैं। उन्होंने कहा कि खैरे ने उन्हें यह बात बताई थी। शिरसाट की आलोचना करते हुए चतुर्वेदी ने उन्हें गद्दार कहा, जिसने अपनी आत्मा और ईमानदारी बेच दी। उन्होंने

ट्वीट किया, ''मुझे यह बताने के लिए किसी गद्दार की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूं और मैं जहां हूं वहां क्यों हूं।'' उन्होंने कहा, ''शिरसाट ने राजनीति और महिलाओं पर अपने खराब विचार प्रदर्शित किए हैं।'' बाद में, आदित्य ठाकरे ने भी शिरसाट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता 'सड़ी हुई' है।

सिंधिया पर प्रिंयका ने साधा निशाना

प्रियंका गांधी एक संबोधन में बोलीं- अचानक बदली उनकी विचारधारा

प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश में आज महंगाई अपने चरम पर है। यह एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि महंगाई से देश की कमर टूट गई है। देश में महंगाई के साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने के लिए पहुंची हैं। यह क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मणिपुर के बहाने भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कटाक्ष किया। आपको बता दें कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि 2020 में कांग्रेस के नेताओं के साथ मतभेद के बाद उन्होंने भाजपा में जाना बेहतर समझा। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके कांग्रेस छोड़ने से मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी गिर गई थी।

केंद्र पर निशाना : प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश में आज महंगाई अपने चरम पर है। यह एक बड़ा

मुद्दा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि महंगाई से देश की कमर टूट गई है। देश में महंगाई के साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसका जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में रोजगार के अवसर बंद किए जा रहे हैं। अग्निवीर ट्रेनिंग से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपों से अलग राजनीतिक नहीं हो सकती।

भाजपा मध्य प्रदेश चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए खुद को चाचा के रूप में पेश किया। सत्तारूढ़ भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्य की कुल 230 में से 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2018 के चुनावों में भगवा पार्टी ने 109 सीटें जीती थीं, जो 116 के साधारण बहुमत से कम थीं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करके सत्ता बरकरार रखेगी। हालांकि, सिंधिया ने यह अनुमान लगाने से परहेज किया कि साल के अंत में होने वाले 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कितनी सीटें जीतेगी। सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने ग्वालियर-चंबल संभाग की अपनी यात्रा के दौरान यहां संवाददाताओं से कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं जो यह बताऊं की भाजपा कितनी सीटें जीतेगी। लेकिन हम राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।" ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह के ग्वालियर दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ता ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और वे अब नए जोश के साथ चुनाव के लिए काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश की यात्रा पर सिंधिया ने कहा कि हर कोई जानता है कि उन्होंने दिल्ली के साथ कैसा व्यवहार किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में है। आप संयोजक केजरीवाल ने रविवार को सतना में एक अभियान रैली को संबोधित किया और मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण सहित विभिन्न गारंटियों का आश्वासन दिया। उन्होंने मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए खुद को चाचा के रूप में पेश किया। सत्तारूढ़ भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्य की कुल 230 में से 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2018 के चुनावों में भगवा पार्टी ने 109 सीटें जीती थीं, जो 116 के साधारण बहुमत से कम थीं।

मेरिट के आधार पर शिक्षकों को आवंटित होंगे स्कूल

सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से लेकर हायर सेकंडरी तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रदेशभर से अतिथि शिक्षकों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगवाए गए हैं। अब इनकी स्क्रूटनी कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को जारी करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद उम्मीदवारों को स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग करना है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए संकुल प्राचार्यों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अतिथि शिक्षकों के लिए भी संचालनालय ने कुछ गाइडलाइन बनाई हैं।

इंदौर जिले में आने वाले 800 स्कूलों में विभिन्न शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। वहां पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन प्राप्त करने के दौरान संकुल प्राचार्यों को रिक्त पदों के बारे में पोर्टल पर जानकारी देना है। 26 जुलाई को पोर्टल पर स्कूलों में विषयवार रिक्त पद बताए गए। जिन स्कूलों में पैनल नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रमुख व प्राचार्यों को रिक्त पदों के बारे में नोटिस बोर्ड पर जानकारी देना थी। उसके आधार पर अतिथि शिक्षकों से आवेदन मंगवाने थे।

31 जुलाई तक प्रक्रिया होने के बाद स्कूलों में 1 अगस्त को बैठक रखनी है, जिसमें मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित करना है। 5 अगस्त तक सारे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को अपनी-अपनी उपस्थित दर्ज करवाना है। इसके बारे में पोर्टल पर भी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देना है। संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक के आवेदनों के सत्यापन किए जाने की तारीख नहीं बताई है। संकुल प्राचार्य के मूल दस्तावेजों का मिलान कर तत्काल सत्यापन किया जाएगा। संस्था प्रमुख प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। प्री-प्रायमरी अतिथि शिक्षकों के लिए अर्हता डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई)

निर्धारित है। ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अतिथि शिक्षकों को पासवर्ड प्राप्त करने के लिए संचालनालय की लिंक का उपयोग करना है। इतना ही नहीं मोबाइल गुम होने की स्थिति में संचालनालय को ई-मेल के माध्यम से आवेदन-स्कोर कार्ड सहित पुराने-नए मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी देना है। समस्या का निराकरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना होगा। संचालक डीएस कुशवाह ने दिशा-निर्देश दिए है।

महीने के पहले दिन ही मिलेगा वेतन, 15 लाख कर्मियों को होगा फायदा..

मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों से कहा है कि आहरण-संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को निर्देशित करें कि कर्मचारियों को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी न हो। प्रदेश में नियमित, संविदा, स्थाईकर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थीं कि वेतन पांच से 10 तारीख को दिया जा रहा है। चुनावी साल में इस शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया और संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए।

प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में भी शिक्षकों का टोटा है। यही कारण है कि इन स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट प्रणाली (जीएफएमएस) से करने का प्रविधान है। विभाग ने जहां-जहां पोर्टल से नियुक्ति प्रक्रिया में समस्या आ रही है, वहां के लिए विभागीय जिला संयोजकों की देखरेख में समिति बना दी है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। ये वही स्कूल हैं, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 50 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। दोनों ही विभाग सीएम राइज स्कूलों का भी संचालन करते हैं। जिनमें शिक्षकों की पदों को नहीं भर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया, जो इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीए के बराबर लाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की। महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी सरकार ने 15 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की भी घोषणा की थी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि भत्ता 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ाया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 2014 में 30 साल की सेवा पूरी करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीसरे वेतनमान (तृतीय समयमान वेतनमान) का लाभ देने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2023 तक 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (चतुर्थ समयमान वेतनमान) का लाभ भी दिया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि इस डीए बढ़ोतरी के कारण जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि छठे वेतनमान के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में भी आनुपातिक वृद्धि देखने को मिलेगी।

जनता का सुख-दुख मेरा सुख-दुख : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता का सुख-दुख मेरा सुख-दुख है। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूँ। विकास पर्व के तहत पूरे प्रदेश में विकास का महायज्ञ चलाया जा रहा है। अनेक निर्माण एवं विकास कार्यों का शिलान्यास तथा भूमि-पूजन किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई के लिए पानी तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान चकल्दी में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने चकल्दी में 81 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया और चकल्दी में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। अनेक योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पादन कम होता था। खेती में किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब अनेक सिंचाई परियोजनाओं से हर किसान के खेत तक पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आज चकल्दी में लोकार्पित पाटतलाई उद्वहन सिंचाई योजना से पाटतलाई, अमीरगंज एवं पलासपानी जैसे पहाड़ी गाँवों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और तीनों गाँवों के 661 किसानों की 889 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था'

वित्त मंत्री बोलीं- हम लोगों को सपने नहीं दिखाते, उन्हें साकार करते हैं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में मॉर्गन स्टेनली ने भारत को दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। आज उसी मॉर्गन स्टेनली ने भारत को अपग्रेड किया और ऊंची रेटिंग दी।

अविश्वास प्रस्ताव अपने आखिरी चरण में है। आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलने वाले हैं। इन सब के बीच तीसरे दिन की चर्चा की शुरूआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। सबसे पहले उन्होंने वैश्विक आर्थिक स्थिति पर बोलना शुरू किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन के दौरान, नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए था और एनडीए के शासन के दौरान लोगों को पहले से ही लाभ मिल रहा है। यूपीए और एनडीए सरकार के बीच अंतर बताते हुए सीतारमण ने कहा के पहले होता था था 'मिलेगा' और अब होता है मिल गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में मॉर्गन स्टेनली ने भारत को दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया था। भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। आज उसी मॉर्गन स्टेनली ने भारत को अपग्रेड किया और ऊंची रेटिंग दी। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में, हमारी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊपर उठी और आर्थिक विकास हुआ - कोविड के बावजूद। आज, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास को लेकर आशावादी और सकारात्मक होने की एक स्थिति में है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'बनेगा, मिलेगा' जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं हैं। आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? 'बन गए, मिल गए, आ गए।'

भाजपा नेता ने कहा कि यूपीए के दौरान लोग कहते थे 'बिजली आएगी', अब लोग कहते हैं 'बिजली आ गई'। उन्होंने कहा 'गैस कनेक्शन मिलेगा', अब 'गैस कनेक्शन मिल गया'...उन्होंने कहा एयरपोर्ट 'बनेगा', अब एयरपोर्ट 'बन गया'। उन्होंने कहा कि परिवर्तन वास्तविक डिलीवरी के माध्यम से आता है, न कि बोले गए शब्दों के माध्यम से। तुम लोगों को सपने दिखाते हो। हम उनके सपनों को साकार करते हैं। हम सभी को सशक्त बनाने और किसी के तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करते। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने 2014 और 2019 में यूपीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और उन्हें हरा दिया। 2024 में भी यही स्थिति होगी। गृह मंत्री ने कल कहा, यूपीए का नाम बदलने की क्या जरूरत?...इनमें गजब की एकता है. यह समझना मुश्किल है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं या साथ मिलकर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यहां के मोहल्ला क्लीनिक देखने दिल्ली आए। उन्होंने आकर कहा कि इनमें कुछ खास नहीं है और हम निराश हैं। ये उनकी लड़ाई का एक उदाहरण है।

भारत उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप मंच शुरू करेगा : गोयल

ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की सातवीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल से देश में लगभग एक लाख स्टार्टअप का गठन हुआ है और इस कारण नयी दिल्ली इस क्षेत्र में अन्य ब्रिक्स सदस्यों को अपना समर्थन दे सकती है।

भारत निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस साल ब्रिक्स स्टार्टअप मंच की शुरुआत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। उन्होंने ब्रिक्स उद्योग

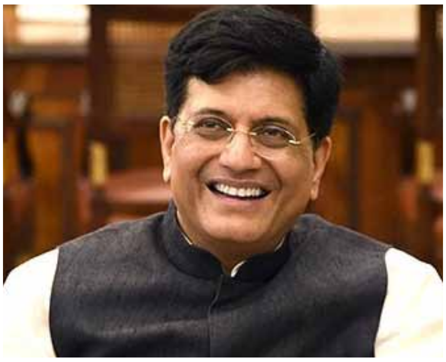

मंत्रियों की सातवीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल से देश में लगभग एक लाख स्टार्टअप का गठन हुआ है और इस कारण नयी दिल्ली इस क्षेत्र में अन्य ब्रिक्स सदस्यों को अपना समर्थन दे सकती है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में हुई इस बैठक में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एक संयुक्त घोषणा को अपनाया। मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटलीकरण, औद्योगीकरण, नवाचार, समावेशन और निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।

गोविंद सिंह ने सिंधिया के चुनाव को चुनौती के संबंध में याचिका वापस ली..

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सोमवार को सिंह के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी को उच्च न्यायालय के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। सिंह ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि एक पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। उनके वकील ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ नामांकन फॉर्म में आवश्यक सभी आवश्यक तथ्य या विवरण प्रस्तुत करना होता है।

मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने 2020 में राज्यसभा के लिए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती वाली अपनी याचिका सोमवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली। सिंह ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। सिंह ने सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश से अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ एक प्राथमिकी के बारे में जानकारी कथित तौर पर छिपाने को लेकर उच्च न्यायालय में उनके चुनाव को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 17 मार्च के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से 13 जुलाई को इनकार करते हुए सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका में मुद्दे तय किए थे। सिंधिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 (फर्जीवाड़ा), 468 (धोखाधड़ी) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी लंबित आपराधिक मामले के दायरे में नहीं आती है।

सिंह की चुनाव याचिका के बाद, उच्च न्यायालय ने केवल प्रारंभिक मुद्दा तय किया था कि क्या केवल प्राथमिकी दर्ज होना ''आपराधिक मामला'' है, जिसका खुलासा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र में किया जाना चाहिए। सिंह ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख कर कहा था कि उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों का सुझाव दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए केवल प्रारंभिक मुद्दा तय किया था। शीर्ष अदालत ने सात जुलाई को सिंह की अपील खारिज कर दी थी और कहा था कि चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के आधार पर विचार करने के बाद ''हमें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती।'' इसके बाद सिंह ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ''उच्चतम न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 के संबंधित आदेश के आधार पर विचार करने के बाद विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में अब पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं है।''

उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सिंह ने शीर्ष अदालत का रुख किया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सोमवार को सिंह के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी को उच्च न्यायालय के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। सिंह ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि एक पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। उनके वकील ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र के साथ नामांकन फॉर्म में आवश्यक सभी आवश्यक तथ्य या विवरण प्रस्तुत करना होता है।

17 साल की नाबालिग को गर्भपात की इजाजत देने से कोर्ट का इनकार

कहा- आपसी सहमति से बने संबंध

कोर्ट ने कहा- लड़की खुद प्रेग्नेंसी किट खरीदकर लाई और फरवरी में ही उसे गर्भधारण होने का पता चल गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता व्यस्क है और उसे पूरी जानकारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपने एक फैसले में 17 साल की नाबालिग लड़की को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने और लड़की को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। लड़की की गर्भावस्था को 24 हफ्ते का समय बीत चुका है। डिविजन बेंच के जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस वाईजी खोबरागडे ने 26 जुलाई को दिए अपने आदेश में ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि लड़की इस महीने ही 18 साल की हो जाएगी और वह लड़के के साथ दिसंबर 2022 से ही रिश्ते में थी। पीठ ने कहा कि पीड़ित लड़की और आरोपी लड़के ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लड़की खुद प्रेग्नेंसी किट खरीदकर लाई और फरवरी में ही उसे गर्भधारण होने का पता चल गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता व्यस्क है और उसे पूरी जानकारी है। अगर याचिकाकर्ता को बच्चे को जन्म नहीं देना था तो वह पहले भी गर्भपात की इजाजत मांग सकती थी।

20 हफ्ते के बाद गर्भपात के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी

नाबालिग लड़की ने अपनी मां के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पोक्सो कानून के तहत गर्भपात कराने की मांग की गई है क्योंकि लड़की खुद नाबालिग है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के तहत अगर गर्भावस्था को 20 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है तो गर्भपात के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। बच्चे और मां की जान के खतरे को देखते हुए कोर्ट मंजूरी देते हैं। इस याचिका में कहा गया है कि बच्चे को जन्म देने से नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा।

जन्म के बाद बच्चा गोद दे सकती है पीड़िता

कोर्ट ने कहा कि बच्चे की डिलीवरी में अब सिर्फ 15 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में लड़की स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। बच्चे के जन्म के बाद वह उसे किसी को गोद देने के लिए स्वतंत्र है।

बांसुरी स्वराज बोलीं- 2015 से अपनी अक्षमता का बहाना बना रही आप

बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह विधेयक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दिल्ली में नौकरशाही के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे दिल्ली के लोगों को न्याय देगा।

भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज ने शनिवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह 'झगड़ालू' और 'निकम्मी' सरकार है। उन्होंने दिल्ली सेवा विधेयक पर भी राष्ट्रपति को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब कानून के मुताबिक काम होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2015 से AAP सरकार अपनी अक्षमता का बहाना बना रही है। यह एक 'झगड़लू' और 'निकम्मी' सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार हो जो हर बात पर उपराज्यपाल ने लड़ाई करती है, मीडिया के समक्ष अपनी बेबसी व्यक्त करती है और हमेशा अधिकारियों को प्रताड़ित करती है। उन्होंने कहा कि मैं विधेयक (दिल्ली सेवा विधेयक) पारित करने के लिए राष्ट्रपति को बधाई देती हूं। अब बिल पास हो गया है तो दिल्ली में प्रशासन कानून के मुताबिक काम करेगा।

बांसुरी स्वराज ने क्या कहा : बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह विधेयक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दिल्ली में नौकरशाही के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे दिल्ली के लोगों को न्याय देगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक की गजट अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है जो अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में उचित प्रशासन और विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित दिल्ली सर्विस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बिल अब कानून बन गया है। दिल्ली की जनता को बहुत-बहुत बधाई!

दिल्ली सेवा विधेयक कानून

दिल्ली सेवा विधेयक जो अब कानून बन गया है, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश का स्थान लेना है। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर केंद्र सरकार को अधिकार देने वाले विधेयक का विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे 'अलोकतांत्रिक' कागज़ का टुकड़ा करार दिया। विपक्षी गठबंधन को I.N.D.I.A के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले गुट, जिसे बीआरएस कहा जाता है, ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके विपरीत, ओडिशा से बीजू जनता दल (बीजेडी) और आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

स्मारक को गिराकर सरकारी आवास बनाने के आरोप में IAS निलंबित

साल की शुरुआत मे दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने स्मारक के विध्वंस के बाद आधिकारिक आवास के निर्माण के लिए राय को नोटिस दिया था। यह स्मारक पठान काल का एक 'महल' था और सैयद वंश के खिज्र खान की आरे से स्थापित खिजराबाद शहर का एकमात्र अवशेष था, जो दक्षिण-पूर्व दिल्ली में लाजपत नगर के पास जल विहार क्षेत्र में स्थित था।

गृह मंत्रालय ने एक स्मारक को गिराने और सरकारी आवास के निर्माण के आरोपी 2007 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, राय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है, 'भारत के राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969 के नियम 3 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदित प्रकाश राय, आईएएस (एजीएमयूटीः 2007) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।'

आदेश में कहा गया है, 'यह आदेश दिया जाता है कि जिस अवधि के लिए यह आदेश लागू रहेगा, उस अवधि के दौरान उदित प्रकाश राय, आईएएस (एजीएमयूटीः 2007) का मुख्यालय मिजोरम होगा और उक्त उदित प्रकाश राय, आईएएस (एजीएमयूटीः 2007) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल अगस्त में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को 'अनुचित लाभ' पहुंचाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राय ने आय से अधिक संपत्ति के दो मामलों में कार्यकारी अभियंता पीएस मीणा को एक तरह से बरी कर दिया था। एक में उनके बेटे और दूसरे में उनकी पत्नी की संलिप्तता की बात कही गई थी। उन पर आरोप था कि वह दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 15वीं शताब्दी के एक स्मारक के विध्वंस के बाद एक आधिकारिक आवास के निर्माण में कथित रूप से शामिल थे। इस साल की शुरुआत मे दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने स्मारक के विध्वंस के बाद आधिकारिक आवास के निर्माण के लिए राय को नोटिस दिया था। यह स्मारक पठान काल का एक 'महल' था और सैयद वंश के खिज्र खान की आरे से स्थापित खिजराबाद शहर का एकमात्र अवशेष था, जो दक्षिण-पूर्व दिल्ली में लाजपत नगर के पास जल विहार क्षेत्र में स्थित था।

यूरिक एसिड से बचना है तो सुधारें लाइफ स्टाइल...

आजकल लोगों में यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। असल में असंतुलित भोजन, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस और नींद पूरी न लेना यूरिक एसिड के मुख्य कारण हैं। शरीर में अलग-अलग तरह के दर्द होते हैं जिनका बड़ा कारण यूरिक एसिड है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है, मगर कई बार यह शरीर में रह जाता है जिससे यूरिक एसिड के साथ-साथ और भी कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं।

कारण और निदान

शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हैं, मसलन-गलत खान-पान। जरूरत से ज्यादा मीठा, प्रोटीन और फ्रूक्टोस युक्त भोजन। सी फूड इत्यादि। मैनोपोज के बाद औरतों के शरीर में हार्मोनल चेंजेज की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करने होंगे और खानपान पर भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें। खूब सारा पानी पीयें। शरीर को हाइड्रेट रखें। ताजे फलों का रस, नारियल पानी, ग्रीन टी, नींबू विटामिन सी, डी, ई से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हरी सब्जियां जैसे-लौकी, धनिया लें। हर रोज लहसुन का सेवन करें। सुबह-शाम 45 मिनट सैर करें। खूब सलाद खायें। फाइबर युक्त भोजन करें। छोटी इलायची, अजवायन का प्रयोग करें। सेब यूरिक एसिट को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। सुबह उठकर अखरोट और बादाम का सेवन करने से भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।

अधिक प्रोटीन सेवन न करें

यूरिक एसिड में एसिडिक चीजें, हाई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे- मटर, पालक, आलू, भिंडी का सेवन न करें। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बनी चीजें भी न लें। चाय, कॉफी का अधिक सेवन न करें। शराब, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस न लें। पनीर, फैट मिल्क, दही न लें। दही की जगह लस्सी ले सकते हैं। यूरिक एसिड की समस्या हो तो बिना छिलके वाली ऐसी दालें खानी चाहिए जिनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन न हो। इसके अलावा मूंग दाल, राजमा, काले चने, उड़द, सोयाबीन, छिलके वाली मसूर दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत महत्व है। अगर हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम किसी भी बीमारी (बैक्टीरिया या वायरस) से आसानी से लड़ सकते हैं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और लाइफ स्टाइल को ऐसा रखें कि आप स्वस्थ रहें।

क्या है यूरिक एसिड : यह एक कार्बोनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से बना होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। जब किडनी शरीर में इन तत्वों को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती तो ये गैस हड्डियों में जमा होने लगती है जिस वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन और कसाव होने लगता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह गठिया, गाउट, आर्थराइटिस और किडनी की बीमारी होने का कारण बन जाता है। इससे शरीर में, जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगती है।

देश में पहनावे की औपनिवेशिक मानसिकता

दिल्ली के एक रेस्तरां में एक महिला को साड़ी पहने होने की वजह से प्रवेश नहीं दिया गया। महिला को मैनेजर ने कहा कि साड़ी स्मार्ट कैजुअल ड्रेस कोड में नहीं आती है। महिला की ओर से एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें यह घटना दर्ज है। महिला होटल के एक कर्मचारी से पूछती है कि क्या साड़ी की अनुमति नहीं है? कर्मचारी जवाब देता है कि साड़ी को स्मार्ट कैजुअल के रूप में नहीं गिना जाता है और रेस्तरां केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है।

दूसरी ओर, रेस्तरां ने अपने बयान में कहा है कि महिला ने उनके स्टाफ से झगड़ा किया, क्योंकि उन्हें अंदर जाने के लिए इंतजार करने को कहा गया था। उनका पहले से रिजर्वेशन नहीं था। रेस्तरां ने माफी भी मांगी है और कहा है कि मैनेजर ने ऐसा इसलिए कहा ताकि महिला चली जाए और स्थिति को संभाला जा सके। इस पर महिला का जवाब था कि हमारे देश में अगर साड़ी को स्मार्ट आउटफिट नहीं माना जाता, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि साड़ी और मानसिकता की लड़ाई है। सोशल मीडिया से इंगित होता है कि इस पर लोगों में भारी नाराजगी है। इसके विरोध में महिलाएं साड़ी पहन कर पोस्ट कर रही हैं। लोग उस रेस्तरां को जीरो रेटिंग दे रहे हैं और बहिष्कार करने को कह रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखा है और रेस्तरां के अधिकारियों को भी तलब किया है। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन भी किया।

इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि हमारे कपड़े ही हमारी पहचान हैं। कम से कम शहरों में महिलाएं अपने पहनावे को लेकर आजाद हैं, लेकिन ड्रेस कोड बनाने और महिलाओं को उनके पहनावे के लिए निशाना बनाये जाने की भी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि होटल और रेस्तरां में पहनावे को लेकर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया हो। कई बार पुरुषों के भी औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार होने की घटनाएं हुई हैं।

अंग्रेज चले गये, लेकिन मानसिक गुलामी के उनके चिह्न आज भी देश में मौजूद हैं, जो ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आते रहते हैं। यह एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि मानसिकता का मामला है। हम एक ओर अंग्रेजों की गुलामी की प्रथाओं से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक वर्ग अब भी उन्हीं विचारों से जकड़ा हुआ है। कुछ समय पहले जाने-माने युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल को दिल्ली के राजीव गांधी चौक, जो कभी कनॉट प्लेस कहलाता था, के एक रेस्तरां में जाने से इसलिए रोक दिया गया था कि उनके कंधे पर गमछा था।

साहित्य कला अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल झारखंड से हैं। इस घटना की सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई थी। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में युवा और साहित्यकार आगे आये थे। दिल्ली का कनॉट प्लेस का नाम भले ही राजीव चौक कर दिया हो, वह दिल्ली के अभिजात्य वर्ग के खरीदने-टहलने वाला इलाका रहा है। आजादी के 75 वर्ष बीत गये। इस दौरान बदलाव आया है, लेकिन मानसिकता में अब भी कुछ औपनिवेशिक तत्व मौजूद हैं। हम पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाये हैं।

हमारे अनेक विश्वविद्यालयों ने दीक्षांत समारोह में गाउन के स्थान पर भारतीय परिधान कुर्ता-पायजामा, साड़ी आदि का इस्तेमाल शुरू किया है। आइआइटी जैसे संस्थान भी इसे अपना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह में छात्राओं के लिए साड़ी और छात्रों के लिए कुर्ता पहना तय है। पूरे दक्षिण एशिया में साड़ी महिलाओं का परिधान है। चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो अथवा पाकिस्तान, सब जगह साड़ी खूब पहनी जाती है।

मुझे लगभग एक दशक पहले एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान जाने का मौका मिला था। वहां मैंने पाया कि अधिकतर महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं, लेकिन वे साड़ी भी पहनती हैं। इस्लामाबाद के जिस पांच सितारा सेरेना होटल में यह प्रतिनिधिमंडल ठहरा हुआ था, वहां कार्यरत महिलाओं के लिए ड्रेस कोड साड़ी था। यह सुखद आश्चर्य की तरह था कि वहां काम रहीं सभी महिलाएं साड़ी पहनी हुई थीं।

हालांकि हाल में पाकिस्तान में एक महिला सांसद जब साड़ी पहन कर संसद पहुंची थीं, तो उस पर आपत्ति की गयी थी। एमक्यूएम सांसद नसरीन जलील संसद में साड़ी पहन कर पहुंची थीं, जिस पर जमियत उलेमा-ए-इस्लाम फज्ल के एक सांसद ने कड़ी आपत्ति जतायी थी।

हमें यह याद रखना चाहिए कि हम गांधी की परंपरा के देश हैं और हाल में हमने गांधी की 150वीं जन्मशती मनायी है। वे 1888 में कानून के एक छात्र के रूप में इंग्लैंड में सूट पहनते थे, लेकिन भारत में उन्होंने एक-एक कर सभी वस्त्र त्याग दिये और सिर्फ धोती में दिखे। वर्ष 1917 में गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, तब वे काठियावाड़ी पोशाक पहने हुए थे। जब उन्होंने सुना कि नील फैक्ट्रियों के मालिक निम्न वर्ग की औरतों और मर्दों को जूते नहीं पहनने देते हैं, तो उन्होंने तुरंत जूते पहनना बंद कर दिया।

दूसरी यात्रा में एक निर्धन महिला को अपना चोगा सौंप दिया था और इसके बाद उन्होंने चोगा ओढ़ना बंद कर दिया। जब वे 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की लड़ाई में शामिल हुए, तो उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी में जितना कपड़ा लगता है, उसमें चार लोगों का तन ढका जा सकता है। उसके बाद उन्होंने पगड़ी पहनना छोड़ दिया था। आजादी की लड़ाई के दौर में नेताओं की पहली पसंद धोती-कुर्ता और गांधी टोपी थी और महिलाएं साड़ी पहनती थीं।

बाद में धोती-कुर्ता की जगह पायजामा-कुर्ता ने ले ली, लेकिन महिला नेताओं की पसंद साड़ी बनी रही। अगली पीढ़ी में गांधी टोपी का चलन धीरे-धीरे कम होने लगा। फिलहाल आप, सपा और कांग्रेस सेवा दल जैसे खास दलों व संगठनों को छोड़ कर अन्य दलों के कुछेक नेता ही टोपी पहनते हैं। पिछले पांच-सात साल में पहनावे का ट्रेंड बदला है। राजनीति की नयी पीढ़ी की पसंद अब पैंट-शर्ट या सूट-बूट हो गया है, लेकिन अधिकतर महिला नेताओं की पसंद आज भी साड़ी है।

हम देश-काल और परिस्थितियों के अनुसार पहनावे के बारे में निर्णय लें, तो बेहतर होगा। हम आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में ऐसी घटनाएं चिंता जगाती हैं कि हम अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त क्यों नहीं हो पाये हैं। इस पर व्यापक विमर्श की जरूरत है।

बालों को प्रोटेक्ट भी करता है डुरैग

डुरैग में खुद को स्टाइल करने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। डुरैग को आमतौर पर वेव कैप भी कहा जाता है। यह आपके सिर को कवर करता है और बालों को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। साथ ही सोते समय हेयरस्टाइल को मैसी होने से बचाने में भी यह मददगार है। स्टाइलिश लुक पाने के लिए सिर्फ आउटफिट पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, बल्कि आप बालों को किस तरह से स्टाइल करते हैं, यह भी उतना अहम् है। तरह-तरह के हेयरस्टाइल के अलावा कुछ हेयर एसेसरीज भी आपके लुक को चिक बना सकती हैं। आपने कैप से लेकर बंडाना तो कई बार पहना होगा, लेकिन आज हम आपको डुरैग के बारे में बता रहे हैं। यह एक ऐसी हेयर एसेसरीज है, जिसे पुरूष व महिलाएं दोनों ही पहनना काफी पसंद करते हैं। वहीं, दूसरी ओर, आपके बालों को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं डुरैग के बारे में-

क्या है डुरैग

डुरैग में खुद को स्टाइल करने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। डुरैग को आमतौर पर वेव कैप भी कहा जाता है। यह आपके सिर को कवर करता है और बालों को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। साथ ही सोते समय हेयरस्टाइल को मैसी होने से बचाने में भी यह मददगार है। वहीं दूसरी ओर, यह आपको चिक लुक

भी देता है।

फ्रिजी हेयर से बचाव

डुरैग पहनने का एक लाभ यह भी है कि इसे पहनने से आपके सिर पर ड्रेडलॉक और वेव्स के विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। डुरैग फ्रिज़ीनेस से बचने में मदद करता है और आपके हेयरलॉक्स को पूरे दिन साफ रखता है। ऐसे में अगर आप स्टाइलिश तरीके से अपने बालों की केयर करना चाहते हैं तो ऐसे में डुरैग को पहना जा सकता है।

ऐसे पहनें डुरैग

डुरैग पहनकर अगर आप एक स्टाइलिश लुक पाना चाहते हैं तो आपको इसे पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे- जब आप डुरैग पहन रहे हैं तो इसे कुछ इस तरह बांधें कि यह आपके फोरहेड पर फ्लैट व स्मूद नजर आए। इसे यूं ही लपेटने से बचें। अगर आप डुरैग पहनकर सो रहे हैं तो ऐसे में आप इसे हेडबैंड के साथ सिक्योर करें, ताकि यह रात को सोते समय खुले नहीं।

दें डिफरेंट लुक

फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, डुरैग को पहनकर आप कई डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। मसलन, आप इसे कुछ इस तरह पहनें कि यह आपके सारे बालों को कवर करे और आप इसकी लेंथ को ऐसे ही शोल्डर पर रहने दें। इसके अलावा, अगर आप चाहें तो साइड टाई डुरैग लुक भी कैरी कर सकते हैं। इसमें डुरैग को पीछे

बालों के लिए फायदेमंद है 'कोकोनट मिल्क'

कई महिलाएं कितने भी शैंपू, क्रीम और ब्यूटी ट्रीटमेंट क्यों ना करा लें, लेकिन उनके बालों में समस्या बनी रहती है। इन दिनों बालों में डैंड्रफ और बाल टूटने की समस्या लोगों में खूब देखी जा रही है। प्रदूषण और गलत खान-पान के कारण बालों में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है। ऐसे में बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं। ऐसे में बाजार में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो खास बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट देने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों में घरेलू चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप नारियल के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नारियल के तेल के फायदे

1 बाल केराटिन से बने होते हैं, ऐसे में हई प्रोटीन युक्त नारियल दूध का इस्तेमाल करने से बाल मजहबूत बनते हैं।

2 नारियल दूध में पाए जाने वाले विटामिन आपके बालों को स्वस्थ, मजबूत और नमीयुक्त रख सकते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ई, साथ ही विटामिन बी जैसे बी-1, बी-3, बी-5, और बी-6 शामिल हैं।

3 नारियल के तेल को बालों के क्यूटिकल्स को मजबूत

बनाने के लिए जाना जाता है ताकि पानी और हानिकारक पदार्थ से बालों को नुकसान ना हो।

4 नारियल के दूध में नैचुरल फैटी एसिड होते हैं, जो बालों को मॉइश्चराइज रखते हैं। साथ ही खराब बालों को ठीक करने के लिए भी ये अच्छा विकल्प है।

कैसे करें मिल्क का इस्तेमाल

आप बालों में कोकोनट मिल्क से बना हेयर मास्क लगा सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप नारियल के दूध में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं। अच्छे से मिलाने के बाद इसे स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक 30 मिनट के लिए लगाएं और वॉश करें।

घर में करें नारियल का दूध तैयार

वैसे तो ये दूध बाजार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप इसे घर में बनाना चाहती हैं तो फ्रेश नारियल को छील कर छोटे-छोटे टुकड़े काट लें। फिर उसे मिक्सी में पीस कर उसमें से दूध निकाल लें।

गोलगप्पा...
जितने नाम, उतने ज़ायके

• शिखर चंद जैन

पुरुष हों या महिलाएं सबकी पसंदीदा डिश है चटपटा गोलगप्पा। शॉपिंग करने जाएं या शादी ब्याह में दावत खाने, तमाम व्यंजनों के बीच सबको पसंद आता है गोलगप्पा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि गोलगप्पे को देश भर में कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है ।

पकौड़ी

आप और हम पकौड़ी भले ही बेसन या मूंगदाल से बनी डिश को कहते हों लेकिन गुजरात के कुछ हिस्सों में गोलगप्पे को पकौड़ी कहते हैं। इसके भरावन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी ज़रा अलग होती है। कहीं इसमें बेसन के लच्छे, मीठी चटनी और कच्चे प्याज डाले जाते हैं, तो कहीं छोटे-छोटे कटे हुए उबले आलू और उबली हुई साबुत हरी मूंग की फिलिंग भी की जाती है। इसे खजूर की चटनी के साथ खाने पर मज़ा आ जाता है।

गुपचुप

मध्यप्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी इसे गुपचुप कहकर पुकारते हैं। छत्तीसगढ़ में भी गोलगप्पों को गुपचुप कहते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलिंग के रूप में मैश किए उबले हुए आलू और उबली हुई पीली मटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पानी आमतौर पर इमली या अमचूर से बनाते हैं।

फुलकी

आमतौर पर फुलकी चपाती या रोटी को कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में फुलकी गोलगप्पों को कहते हैं। यहां के गोलगप्पों का स्वाद भी दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है। इसके भरावन में ताज़ा मीठा दही इस्तेमाल किया जाता है जो इसे अलग टेस्ट देता है।

पुचका

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गोलगप्पे को पुचका के नाम से जाना जाता है। उच्चारण में फर्क के कारण बंगाली या असमिया लोग इसे फुचका और राजस्थान समुदाय के कुछ लोग पिचका भी कहते हैं। यहां गोलगप्पों में मैश किया गया उबला आलू, उबले हुए देसी चने, धनिया पत्ती, तरह- तरह के मसाले मिलाकर स्टफिंग की जाती है। कहीं इमली का पानी तो कहीं, नींबू पानी में पुदीना मिलाकर सर्व किया जाता है।

टिक्की

उत्तरप्रदेश में कुछ खास इलाकों में और मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में गोलगप्पों को टिक्की कहकर पुकारते हैं। यहां भरावन के रूप में उबले आलू और उबले हुए काबुली चनों में मसाले मिलाकर डालते हैं। पानी आमतौर पर इमली का इस्तेमाल किया जाता है।

पानीपुरी

देश के कई हिस्सों में इसे पानीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में यह नाम विशेष रूप से प्रचलित है। मुंबईया फिल्मों में जब भी इसका जिक्र होता है या कोई ठेले वाला दिखाया जाता है, तो पानीपुरी ही दिखाया जाता है।

पतासी या पताशे

राजस्थान, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के कई हिस्सों में गोलगप्पे पतासी या पताशे के नाम से जानी जाती है। यहां सूजी के पतासे भी बनते हैं और आटे और मैदे के भी। इनमें उबले आलू और पीली मटर की फिलिंग की जाती है। कहीं- कहीं इसे बूंदी वाले पानी के साथ सर्व किया जाता है। बड़े शहरों में सात-आठ अलग-अलग स्वाद वाला पानी तैयार किया जाता है, जिसमें पुदीने का, जीरे का और लहसुन का स्वाद होता है। कई जगह तो भरावन में बारीक कटा हुआ प्याज भी इस्तेमाल किया जाता है।

पड़ाका

उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में गोलगप्पे को पड़ाका के नाम से जाना जाता है। यहां आटे और सूजी के पड़ाके तरह-तरह के मसालों वाले अलग अलग तरह के पानी के साथ सर्व किए जाते हैं। यहां भरावन के बजाय पानी के स्वाद पर ही जोर ज्यादा दिया जाता है। कई जगह पड़ाकों में बिना कुछ भरे सिर्फ मसालेदार पानी डालकर खाया-खिलाया जाता है।

गोलगप्पा

गोलगप्पा इसका यूनिवर्सल नाम है। देश के किसी भी कोने में जाइए और आपको इसका स्थानीय नाम मालूम नहीं है तो भी आप बेहिचक गोलगप्पे के नाम से पूछिए, सब जान जाएंगे।

प्रेग्नेंसी में गैस और ब्लोटिंग की समस्या से हो गई हैं परेशान आजमाएं ये उपाय

प्रेग्नेंसी के दौरान हर महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं। वहीं महिला को कई तरह की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में पेट दर्द, ब्लोटिंग और गैस आदि की समस्या से निजात पाने के लिए आप यह उपाय अपना सकती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान पेट संबंधी कई समस्याएं होती हैं। इस समस्या में पेट में दर्द, ब्लोटिंग और गैस आदि शामिल है। बता दें कि प्रेग्नेंसी के दौरान यह समस्याएं गर्भाशय में दबाव बढ़ने के कारण होता है। ऐसे में महिलाओं का पेट साफ होना बेहद जरूरी होता है। जिससे कि उन्हें कब्ज या पाचन जैसी समस्याएं न हों। आइए जानते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स से पेट साफ करने के आसान उपायों के बारे में...

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार एक प्रेग्नेंट महिला को कम से कम रोजाना 10 कप पानी पीना चाहिए। दरअसल, पानी भोजन को पचाने में मदद करता है और गैस बनने से रोकता है। अगर आप प्रेग्नेंसी में पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं। तो इससे आपका शरीर भी हाइड्रेट रहता है। वहीं शरीर के हाइड्रेट रहने से कब्ज की समस्या नहीं होती है और पेट भी साफ रहता है।

फाइबर इनटेक बढ़ाएं

गर्भवती महिला को अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फाइबर का सेवन करने से गैस आदि की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन फाइबर कब्ज की समस्या में भी आराम देता है। गैस बनने का एक बड़ा कारण कब्ज भी है। फाइबर मौजूद पानी मल को नर्म करता है और इसे त्यागने में ज्यादा समस्या नहीं होती है। अगर आपने डाइट में फाइबर इनटेक की मात्रा को बढ़ाई है तो फाइबर वाले फूड्स का कम मात्रा में सेवन करें। इसके साथ ही अपने भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। जिससे कि इसे पचने में आसानी हो।

एक्सरसाइज करें

प्रेग्नेंसी में आप एक्सरसाइज की मदद से भी पाचन समस्या से निजात पा सकती हैं। साथ ही कब्ज से भी राहत मिलती है। ऐसे में महिलाओं को रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अपने मन से एक्सरसाइज न करें। आप वॉकिंग और ऐरोबिक एक्रससाइज अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर सकती हैं। अधिक से अधिक खुद को फिजिकली एक्टिव रखें।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स न पिएं

प्रेग्नेंसी में पेट से संबंधित समस्या तब भी हो सकती है, जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक या खास किस्म के शर्बत का सेवन करती हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक और खास किस्म के शरबत में जैसे कोला, सोडा ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या स्पार्कलिंग वॉटर शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को फ्रुक्टोज आसानी से हजम नहीं होता है। यह एक तरह का शुगर है, जो फलों में पाया जाता है। वहीं कुछ मिठाइयों या डेजर्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में इनका सेवन करने से पाचन खराब हो सकता है।

तनाव से दूर रहें

प्रेग्नेंसी के दिनों में तनाव लेना जरा भी सही नहीं है। ऐसे स्ट्रेस लेने से पेट संबंधी समस्या होने लगती हैं। जब प्रेग्नेंट महिला बहुत ज्यादा तनाव लेती है तो कई बार उनकी सांस उखड़ने लगती है। सीने में जलन के अलावा गैस बनने की शिकायत होती है। इसलिए तनाव के स्तर को कम करें। स्ट्रेस के कारण बनने वाली गैस कई बार इरीटेबल बाउल सिंड्रोम का लक्षण भी हो सकती हैं। इस दौरान आपको गैस, क्रैंपिंग, कब्ज, ब्लोटिंग और डायरिया आदि भी हो सकता है।

बारिश के मौसम में भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन...

मानसून के महीनों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है। इसलिए इस दौरान पोषण का ध्यान रखना जरुरी है। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिनका इस सीजन में सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए इन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं-

बारिश का मौसम शुरू होते ही गर्मी के तपिश भरे दिनों से राहत मिल जाती है। सिर्फ राहत ही नहीं ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, जो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। मानसून के महीनों में लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि इस दौरान संक्रमण फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है। संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए लोगों को अच्छी डाइट लेने की सलाह दी जाती है। हालाँकि, इसके बावजूद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल, मानसून के महीनों में पोषण का ध्यान रखना जरुरी है। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जिनका इस सीजन में सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए इन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं-

स्ट्रीट फ़ूड से करें परहेज- बारिश के मौसम में स्ट्रीट फ़ूड से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में बारिश के कारण हर तरफ गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट फ़ूड प्रदूषित हो जाते हैं। प्रदूषित स्ट्रीट फ़ूड का सेवन करने से पेट ख़राब हो सकता है। गंभीर समस्या की बात करें तो स्ट्रीट फ़ूड फूड पॉइज़निंग का कारण भी बन सकता है।

पत्तेदार सब्जियों का करें संभलकर सेवन- बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाते समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल, इस मौसम में इन सब्जियों में कीड़ें लग जाते हैं, जिनका सेवन करने से आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा बारिश के पानी की वजह से ये सब्जियां भी प्रदूषित हो जाती है। इसलिए इनको अच्छे से देखकर और साफ़ कर के ही खाएं।

तली हुई चीजों का कम करें सेवन- मानसून के मौसम में बरसात होते ही लोगों का चार और पकोड़ों का सेवन करने का मन करने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मौसम में तली हुई चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। मानसून में आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसलिए आपको गैस, एसिडिटी, सूजन, मतली, उल्टी, पेट की परेशानी, ऐंठन, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

डेयरी उत्पादों का सेवन करना भी सुरक्षित नहीं- बारिश के मौसम में दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। दरअसल, इस मौसम में हवा में नमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेयरी उत्पादों में बैक्टीरिया ज्यादा विकास होने लगता है और वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब दूध, पनीर जैसी चीजों का सेवन करने से पेट का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

बरसात के दिनों में हेपेटाइटिस का जोखिम होता है अधिक

जानिए इस रोग से कैसे करें बचाव

हेपेटाइटिस, लिवर में होने वाले सूजन की बीमारी है, जो कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती है। लिवर में होने वाली सूजन की स्थिति कुछ प्रकार के वायरस (वायरल हेपेटाइटिस), रसायन, दवाओं, शराब,आनुवंशिक विकारों के कारण हो सकती है। साल 2019 में हेपेटाइटिस-बी के कारण आठ लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। वैश्विक स्तर पर इस रोग के जोखिमों को कम करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है।

डॉक्टर कहते हैं, बरसात के दिनों में हेपेटाइटिस का जोखिम और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि सभी लोगों को इससे बचाव के तरीकों का पालन करते रहना चाहिए। मानसून के इन दिनों में दूषित जल के कारण इस रोग का खतरा काफी अधिक हो जाता है।

मानसून के दिनों में जोखिम

डॉक्टर कहते हैं, हेपेटाइटिस कई प्रकार का हो सकता है, हालांकि मानसून के दौरान हेपेटाइटिस-ए और ई के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। ये दोनों ही दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलते हैं। वैसे तो हेपेटाइटिस को अल्पकालिक समस्या के रूप में जाना जाता है, पर आधे से अधिक लोगों में इसके दीर्घकालिक संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। लिवर में होने वाली किसी भी समस्या का असर पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करने वाला हो सकता है, इसलिए इसके जोखिमों को कम करने के लिए प्रयास किए जाते रहने चाहिए।

हेपेटाइटिस-ए का खतरा अधिक

डॉक्टर बताते हैं, हेपेटाइटिस ए अत्यधिक संक्रामक है, हालांकि लेकिन लंबे समय तक लिवर के स्वास्थ्य पर बिना कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले यह कुछ हफ्तों या महीनों तक भी रह सकता है। हेपेटाइटिस-ए, अस्वास्थ्यकर भोजन या दूषित पानी से फैलता है यही कारण है कि मानसून के मौसम में यह आम है। संक्रमण का कोई विशिष्ट उपचार तो नहीं है और इसलिए इसे फैलने से रोकना महत्वपूर्ण हो जाता है है। जिन लोगों को क्रोनिक स्वास्थ्य समस्याएं या पहले से ही लिवर की गंभीर है, उन्हें इसके कारण लिवर फेलियर और यहां तक कि मृत्यु का भी खतरा होता है।

हेपेटाइटिस ए और ई से बचें?

- हेपेटाइटिस-ए और ई आमतौर पर भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है, यही कारण है कि बरसात के दिनों में इसका जोखिम सबसे अधिक देखा जाता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसके खतरे को कम किया जा सकता है।
- बाथरूम का उपयोग करने के बाद और खाने से पहले हाथ धोएं।
- यह सुनिश्चित करना जरूरी कि भोजन अच्छी तरह से पकाया गया है।
- यात्रा के दौरान केवल बोतलबंद पानी पीना चाहिए।
- उन फलों और सब्जियों से परहेज करें जिनमें थोड़ी भी सड़न हो।
- फलों-सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही इसका सेवन किया जाना चाहिए।

भगवान शिव का अपमान देखकर सती ने जो किया वह आज भी...

दिव्य प्रेम का महान आदर्श

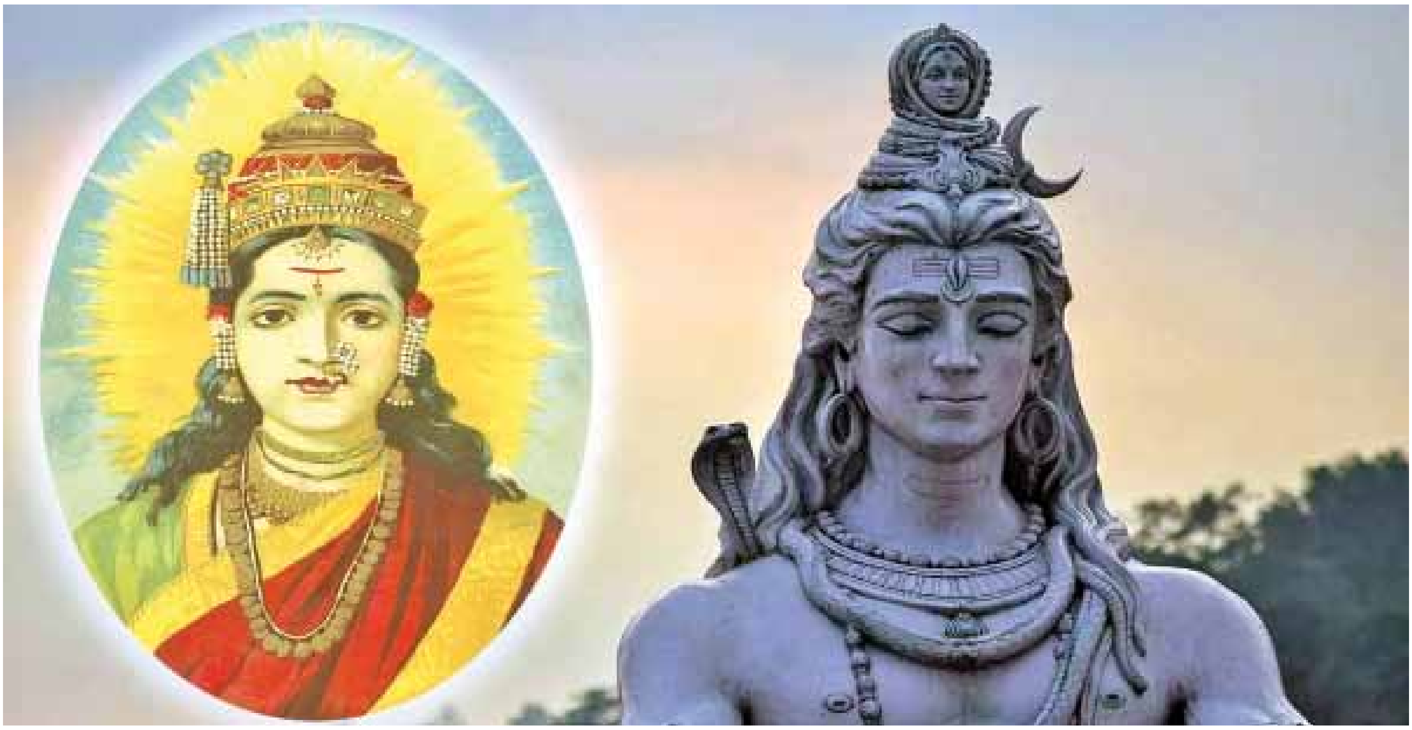

भगवान शंकर के समझाने पर भी सतीजी नहीं मानीं और आंखों में आंसू भरकर रोने लगीं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। दक्षयज्ञ में पहुंचने पर वहां सती को भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया।

सती के पिता महाराज दक्ष को ब्रह्माजी ने प्रजापति नायक के पद पर अभिषिक्त किया। महान अधिकार मिलने से दक्ष के मन में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है, जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। एक बार ब्रह्माजी की सभा में बड़े-बड़े ऋषि, देवता और मुनि उपस्थित हुए। उस सभा में भगवान शंकर भी विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पधारे। उनके स्वागत में सभी सभापति उठकर खड़े हो गये। केवल ब्रह्माजी और भगवान शंकर अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया लेकिन भगवान शंकर का बैठे रहना उन्हें नागवार गुजरा। उन्हें इस बात से विशेष कष्ट हुआ कि ब्रह्माजी तो चलो उनके पिता थे लेकिन शंकर जी तो दामाद थे। उन्होंने उठकर उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में भगवान शंकर की निंदा की और उन्हें शाप तक दे डाला। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिवजी से वैर बुद्धि के कारण अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया।

आकाश मार्ग से विमान में बैठकर सभी देवताओं, विद्याधरों और किन्नरियों को जाते हुए देखकर सती ने भगवान शिव से पूछा- भगवन ये लोग कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सतीजी बोलीं, प्रभो पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता पिता से मिले हुए मुझे बहुत समय बीत गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों को भी वहां चलना चाहिए। यह ठीक है कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है किंतु माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाये जाने में कोई हर्ज नहीं है।

शिवजी बोले- इसमें संदेह नहीं कि माता पिता और गुरुजनों आदि के यहां बिना बुलाये भी जाया जा सकता है, परंतु जहां कोई विरोध मानता हो, वहां जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम्हें वहां जाने का विचार त्याग देना चाहिए।

भगवान शंकर के समझाने पर भी सतीजी नहीं मानीं और आंखों में आंसू भरकर रोने लगीं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। दक्षयज्ञ में पहुंचने पर वहां सती को भगवान शिव का कोई भाग नहीं दिखाई दिया। दक्ष ने भी सती का कोई सत्कार नहीं किया। उनकी बहनों ने भी उन्हें देखकर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा दिया। केवल उनकी माता बड़े प्रेम से मिलीं। भगवान शिव का अपमान देखकर सती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दक्ष से कहा, पिताजी जिन भगवान शिव का दो अक्षरों का नाम बातचीत के प्रसंग में अनायास आ जाने पर भी नाम लेने वाले के समस्त पापों का विनाश कर देता है, आप उन्हीं भगवान शिव से द्वेष करते हैं। अतः आपके अंग के संसर्ग से उत्पन्न इस शरीर को मैं तत्काल त्याग दूंगी, क्योंकि यह मेरे लिये कलंक रूप है। ऐसा कहकर सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। सती का यह दिव्य पति प्रेम आज भी महान आदर्श है।

मानसून में भी खिला-खिला रहेगा आपका चेहरा...

स्किन की देखभाल करने के लिए हम सभी न जाने कितनी चीजों का उपयोग करते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो स्किन केयर रूटीन को स्किप करने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्किन केयर रूटीन को स्किप करती हैं, तो इससे आपकी स्किन खराब हो सकती है।

स्किन की देखभाल करने के लिए हम सभी न जाने कितनी चीजों का उपयोग करते हैं। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही हमारी त्वचा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में कम कंफ्यूज हो जाते हैं और स्किन केयर रूटीन में बदलाव कर देते हैं। लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो स्किन केयर रूटीन को स्किप करने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्किन केयर रुटीन को स्किप करने से भले ही उस समय त्वचा में कोई बदलाव न नजर आए। लेकिन कुछ समय बाद से ही आपको इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाले हैं, जो स्किन केयर करते समय करते हैं। बाद में पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। इस आर्टिकल में हम आपको मानसून में भी अपनी स्किन को हेल्दी और नैचुरली ग्लोइंग बनाने के कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

मॉइस्चराइजर

रोजाना सी.टी.एम रूटीन करना जरूरी होता है। वहीं मानसून में स्किन की नमी बढ़ जाती है। इससे स्किन तो हाइड्रेट नजर आती है, लेकिन मौसम में बदलाव होने की वजह से ऐसा लगता है। इसलिए मौसम चाहे जो हो, आपको स्किन केयर रूटीन में कभी भी मॉइश्चराइजर को स्किप करने की गलती नहीं करनी चाहिए।

सनस्क्रीन

बदलते मौसम में और मानसून में कभी ज्यादा धूप होती है तो कभी कम। ऐसे में कई बार हम सनस्क्रीन को अप्लाई करना स्किप कर देते हैं। आप घर में रहें या बाहर, लेकिन रोजाना चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए।

इससे आपकी स्किन पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। जो बाहरी प्रभाव से आपकी त्वचा को डैमेज होने से बचाती है।

लिप केयर

बदलते मौसम में होंठ जरूरत से ज्यादा फटने लगते हैं। या फिर कुछ ज्यादा ही हाइड्रेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि डेली लिप केयर रूटीन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में किसी भी मौसम में लिप केयर रूटीन को स्किप नहीं करना चाहिए। इसलिए सप्ताह में कम से कम 2-3 बार लिप स्क्रब का इस्तेमाल करने के साथ ही रोजाना लिप बाम लगाना चाहिए।

शीट मास्क और सीरम

स्किन में नमी बनाए रखने के लिए मौसम बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं शीट मास्क और सीरम का इस्तेमाल आपके फेस को लंबे समय तदक एजिंग साइंस की समस्या से बचाता है। इसलिए आपको इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप सप्ताह में 3 बार शीट मास्क लगा सकती हैं। तो वहीं रोजाना सीरम का इस्तेमाल फेस पर कर सकती हैं।

वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का कमाल

मिश्रित टीम एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता...

भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और शिव नरवाल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

निशानेबाज ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने शुक्रवार को यहां आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेमे को खुश कर दिया। इस भारतीय जोड़ी ने स्पर्धा के फाइनल में तुर्की की इलायडा तरहान और यूसुफ डिकेच की जोड़ी को 16-10 से पराजित कर देश के पदकों की संख्या दो कर दी।

वहीं भारत इस समय एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर तालिका में दूसरे स्थान पर चल रहा है। जबकि चीन पांच स्वर्ण और दो कांस्य पदक से शीर्ष पर काबिज है। भारतीयों ने क्वालीफिकेशन दौर में शानदार प्रदर्शन किया। जिसमें ईशा ने 290 और नरवाल ने 293 अंक जुटाये। उनका कुल स्कोर 583 रहा जिससे उन्हें क्वालीफिकेशन दौर में शीर्ष पर रहने में मदद मिली और तुर्की की जोड़ी 581 के कुल स्कोर से दूसरे स्थान पर रही।

इसके साथ ही चीन और ईरान ने समान 580 अंक जुटाये लेकिन 'इनर 10' की बदौलत चीन तीसरे स्थान से फाइनल के लिए क्वालीफाई हुआ। पर भारत के राइफल निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन किया और वे क्वालीफिकेशन चरण की बाधा भी पार नहीं कर सके। मेहुली घोष (316.0) और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (314.2) की जोड़ी ने कुल630.2 का स्कोर बनाया और क्वालीफिकेशन दौर में नौवें स्थान पर रहे। वहीं रमिता (313.7) और दिव्यांश सिंह पंवार (314.6) की दूसरी भारतीय जोड़ी कुल 628.3 का स्कोर बनाकर 77 टीमों में 17वें स्थान पर रही। प्रतियोगिता में शीर्ष चार टीमें ही फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं।

चीन के हुआंग युटिंग और शेंग लिहाओ की जोड़ी ने 632.7 अंक से क्वालीफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल क्वालीफाई किया। चीन की इस जोड़ी ने ईरान को 16-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता जबकि फ्रांस ने इस्राइल को 17-9 से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। इससे चीन के पांच स्वर्ण पदक हो गये। महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में परिनाज धालीवाल (118), गनेमत सेखों (118) और दर्शा राठौड़ (115) की टीम 351 अंक बनाकर कांस्य पदक जीतने वाली स्लोवाकिया (359) के बाद चौथे स्थान पर रही। अमेरिका ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर खाता खोला जबकि इटली ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने गुरुवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टीम कांस्य पदक जीता था।

यूएस में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए होगी एक समान गेंद

विश्व में नंबर एक खिलाड़ी और पिछले साल की चैंपियन इगा स्वियातेक उन महिला खिलाड़ियों में शामिल थी जिन्होंने महिला वर्ग में उपयोग लाई जा रही गेंद को पुरुष वर्ग की गेंद की तुलना में हल्का करार दिया था।

अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इस साल पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए एक समान गेंद का उपयोग किया जाएगा जो उन महिला खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने पिछले साल उपयोग में लाई गई गेंद को घटिया करार दिया था। विश्व में नंबर एक खिलाड़ी और पिछले साल की चैंपियन इगा स्वियातेक उन महिला खिलाड़ियों में शामिल थी जिन्होंने महिला वर्ग में उपयोग लाई जा रही गेंद को पुरुष वर्ग की गेंद की तुलना में हल्का करार दिया था। अमेरिकी ओपन चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अकेला टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग गेंदों का उपयोग किया जाता रहा है।

अमेरिकी ओपन की टूर्नामेंट निदेशक स्टेसी एलास्टर ने पिछले साल कुछ खिलाड़ियों से उनकी राय जानी थी। इन खिलाड़ियों ने हल्की गेंद के बजाय भारी गेंद का समर्थन किया था। वर्ष का यह आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्लशिंग मीडोज में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और टेनिस की गेंद बनाने वाले विल्सन के अनुसार इस तरह के कोर्ट के लिए भारी गेंद आदर्श होती है। एलास्टर ने कहा,'' अगर डब्ल्यूटीए गेंद में बदलाव चाहता है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है।

दिल का दौरा पड़ने के बाद सुष्मिता ने पहली बार खुलकर की अपनी सेहत पर बात...

कहा- भगवान की कृपा

सुष्मिता सेन ने लंबे ब्रेक के बाद 2020 में आर्या के साथ दमदार वापसी की। उन्होंने करोड़ों फैंस के दिल में एक बार फिर से अपनी जगह बनाई। लगातार आर्या के दो सुपरहिट सीजन के बाद अब वह जल्द ही आर्या के तीसरे पार्ट में दिखाईस देंगी। इस दौरान उन्होंने एक हार्ट सर्जरी भी कराई क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने कहा कि अबवह बेहतर हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही आर्या वेबसीरीज के तीसरे सीजन और अपनी नयी वेब सीरीज ताली को दर्शकों के सामने लेकर आएंगी। इस साल मार्च में दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में सेन की एंजियोप्लास्टी हुई थी। सुष्मिता सेन (47) ने बुधवार रात सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया था, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत की। इस दौरान एक प्रशंसक ने जब उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो सेन ने कहा कि वह बेहतर हैं। बातचीत के दौरान सेन ने कहा, भगवान की कृपा से ठीक से भोजन कर रही हूं और जल्द स्वस्थ हो रही हूं। मैं यह कोशिश कर रही हूं कि ताली और आर्या 3 को जल्दी से आपके सामने कैसे लाया जाए। पूर्व मिस यूनिवर्स ने कहा कि वह भी आर्या के तीसरे संस्करण के प्रीमियर का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने जून में इस सीरीज की शूटिंग पूरी की थी।

सोनू निगम के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए की गई धोखाधड़ी...

बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को हाल ही में सोशल मीडिया पर एक धोखाधड़ी का पता चला है, जिसे लेकर गायक ने लोगों को चेतावनी दी है। दरअसल, एरिका नाम की एक महिला सोशल मीडिया पर सोनू निगम की मैनेजमेंट टीम से होने का दावा कर रही है और गायक के फैंस से संपर्क कर रही है।

वह महिला सोशल मीडिया पर लोगों को संदेश भेज रही है कि मुझे और मेरी टीम को सोनू निगम के कुछ खास फैंस से संपर्क करने के लिए और उन्हें चुनने के लिए कहा गया है। आप उन कुछ चुनिंदा भाग्यशाली फैंस में से एक हैं, जिन्हें सोनू निगम के साथ मिलने और उनसे आमने-सामने बात करने का मौका मिलेगा। इसके लिए महिला ने गायक के फैंस से पैसों की भी मांग की।

जब इस बात की जानकारी सोनू निगम को हुई तो उन्होंने लोगों को इस शख्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है। गायक ने अभी तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उनके कानूनी सलाहकार और मित्र आशीष जोशी ने कहा कि कुछ महीने पहले भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब एक व्यक्ति ने खुद को सोनू निगम का ईए बताया था और उनके प्रशंसकों से एक फैन आईडी कार्ड के बदले में 50 हजार रुपये की मांग की थी और कहा गया था कि वह फैन कार्ड लोगों को गायक से मिलने, सोनू निगम के मुफ्त कॉन्सर्ट टिकट पाने में मदद करेगा। हमने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने उस व्यक्ति का बैंक खाता ब्लॉक कर दिया था।

अब म्यूजिक करियर पर अधिक फोकस करेंगे आयुष्मान खुराना, बोले- फैंस ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे

आयुष्मान खुराना अपने अभिनय के साथ-साथ गायिकी के लिए भी जाने जाते हैं। पानी दा रंग, साडी गली, नज्म नज्म, मिट्टी दी खुशबू जैसे कई शानदार गाने उन्होंने अपनी आवाज से सजाए हैं। हाल ही में एक्टर का नया गाना 'रातां कालियां' रिलीज हुआ और वह भी हिट रहा है। आयुष्मान के पसंदीदा संगीतकार रोचक कोहली ने इसकी धुन तैयार की। हाल ही में इस गाने के बहाने एक्टर अपने म्यूजिक करियर पर बात करते नजर आए। आयुष्मान खुराना ने कहा कि रातां कालियां गाने को हिट कहा जा रहा है, इससे मैं बेहद खुश हूं। भारतीय और साउथ एशियन दर्शकों से इसे खूब प्यार मिल रहा है। दुनियाभर के फैंस से जो प्यार मिला है, उससे अभिभूत हूं।

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम्।
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः।।

भावार्थ : कौन हैं महादेव, कौन हैं महात्मा, कौन हैं ध्यान का परम लक्ष्य। वह जो अपने भक्तों के सभी पापों (पाप कर्मों) का नाश करने वाला है। वह जो महान पापों का नाश करता है। ऐसे शिव को नमन

हमारा देश हमारा अभिमान

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका
की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136